सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 345 नई दिल्ली, गुरूवार 19 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

कुलगाम मुठभेड़ में एलईटी का शीर्ष कमांडर लतीफ भट ढेर

सीआरपीएफ पर हुए हमले के बाद से ही सुरक्षाबलों ने इलाके में आतंकियों की तलाश की तेज

श्रीनगर.एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी लतीफ भट को मार गिराया है। वह सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। इससे पहले सुरक्षाबलों ने उसके साथी आतंकी उमर निसार डार को भी ढेर कर दिया था।

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने लतीफ को कई बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया और गोलीबारी जारी रखी। जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह सुरक्षाबलों को लतीफ भट के जंगलगाम गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।

तलाशी के दौरान आतंकी के ठिकाने का पता चला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। बताया जा रहा है कि लतीफ की उम्र करीब 23 वर्ष थी। वह कुलगाम जिले के खेबान गांव का रहने वाला था। वर्ष 2025 से उसके लापता होने की बात भी सामने आयी है। उसके परिवार ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मुठभेड़ बुधवार सुबह उस समय शुरू हुई, जब घाटी की मस्जिदों में सुबह की नमाज के लिए अजान होने वाली थी। सुरक्षाबलों ने घेराबंदी में फंसे लतीफ को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया।

उसे लगातार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने किसी भी अपील को स्वीकार नहीं किया। सुरक्षाबलों की ओर से आतंकी को सरेंडर करने के लिए समझाने का वीडियो भी सामने आया था। इसमें जवान उसे हथियार डालकर बाहर आने की अपील करते दिखे। इसके बावजूद लतीफ ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। लतीफ भट पर कुलगाम में सीआरपीएफ के नाके पर हमला करने का आरोप था।

इस घटना में तीन जवान घायल हुए थे। हमले के बाद से ही सुरक्षाबल उसकी तलाश में जुटे थे। अभियान के दौरान उसके साथी उमर निसार डार को भी मार गिराया गया था। कुछ रिपोर्टों में लतीफ को भारत में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी कमांडर बताया गया है। हालांकि, इस दावे की पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है। सुरक्षाबलों की कार्रवाई को इलाके में आतंकवाद के खिलाफ अभियान की अहम सफलता माना जा रहा है।



अमित शाह ने थपथपाई सुरक्षाबलों की पीठ

दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट ढेर हो चुका है। कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर हमला करने वाला लतीफ भागते हुए एक मस्जिद में छिप गया था। जवानों ने आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और फायरिंग जारी रखी। सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन सामने आया है। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकी लतीफ भट आज तड़के कुलगाम में एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इससे एक दिन पहले उसके आतंकी सहयोगी उमर निसार को भी कुलगाम में मार गिराया गया था।

मोदी आज फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में बुधवार को दी गई। 'भारत 2047' थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में उद्योग जगत के दिग्गजों, सीईओ, राजदूतों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वर्ष 2026-27 फिक्की का शताब्दी वर्ष है, क्योंकि संगठन 7 अप्रैल 2027 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा।

यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब भारत 2026-30 की अवधि के लिए दुनिया की सबसे मजबूत प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और उसने चीन, जापान, जर्मनी तथा अमेरिका सहित कई देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और नीतिगत हस्तक्षेपों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

इन उपायों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आर्थिक जोखिमों को कम करने में मदद की है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उद्योग और सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति वाले संकेतक लगातार आर्थिक मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और सेवा क्षेत्र के लचीलेपन ने भारत के शुद्ध ऊर्जा आयातक होने के बावजूद आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली।

वहीं, अगस्त में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और विदेश से आने वाले धन के प्रवाह में मजबूती आई।



'स्वस्थ शरीर के लिए मन का शांत और प्रसन्न होना जरूरी', प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया सुभाषित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया है। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से पीएम मोदी ने लोगों को स्वस्थ शरीर के लिए शांत मन और प्रसन्नता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री की ओर से एक्स पोस्ट में संस्कृत श्लोक, 'शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः। तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः॥' साझा किया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है कि शरीर और मन, ये दोनों ही रोगों के आश्रय-स्थान हैं। इन दोनों का उचित संयोग ही स्वास्थ्य और सुख का मुख्य कारण माना गया है, अर्थात् स्वस्थ शरीर के लिए मन का शांत और प्रसन्न होना भी अति आवश्यक है। पीएम की ओर से साझा किया गया यह श्लोक आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के सूत्रस्थान के अध्याय एक का 55वां श्लोक है।

'राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सांसद को घेरा



जालंधर.एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि को स्वीकार किया है। इसके बावजूद राहुल गांधी वैश्विक मंच पर भारत की 'बेइज्जती' कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा, 'राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को 'आपदा' कह रहे हैं। उन्होंने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।' उन्होंने कहा, आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया की सभी वित्तीय संस्थाएं, चाहे वह विश्व बैंक हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या दूसरे संस्थान हों, वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि को मानती हैं और कहती हैं कि इस वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। आज हम 7.1 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी, उन्हें एक 'डिजास्टर' इकॉनमी दिखती है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं, उनके (राहुल गांधी) मन में कोई गड़बड़ी चल रही है। उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वह खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए वह इसे एक गड़बड़ी मानते हैं। उन्होंने कहा, देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है लेकिन उन्हें (राहुल गांधी) यह तरक्की नहीं दिख रही है। हम अब

राष्ट्रपति मुर्मु श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोहों के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं

भारत के पास विश्व में युवा प्रतिभाओं का सर्वश्रेष्ठ पूल है, जो एसआरसीसी जैसे महाविद्यालयों से परिलक्षित होता है : मुर्मु

नई दिल्ली.ओपन सर्च

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोहों के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तरीय संस्थानों के रूप में विकसित होना चाहिए।

इससे न केवल भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपरपावर बनाने के राष्ट्रीय विजन को साकार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी इन संस्थानों की ओर आकर्षित होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दस वर्षों के दौरान भारत विश्व की सबसे तेजी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। देश में बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, डिजिटल दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, और वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास को हासिल किया गया है। स्टार्टअप के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तैयार हुआ है और 'व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)' को उच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रभावी कल्याणकारी उपाय लागू किए गए हैं कि कोई भी लक्षित लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। हाल के वर्षों में लगभग 50 करोड़ देशवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। अनिश्चितताओं और संघर्षों से घिरे वैश्विक माहौल की तमाम चुनौतियों के बावजूद ये उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

इस कॉलेज के विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की इस मजबूती और सफलता को देखने तथा उससे सीखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे इस सीख का इस्तेमाल हमारी विकास यात्रा को और तेज करने के लिए करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत नई ऊर्जा और नई दृष्टि के साथ वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक भूमिका का विस्तार कर रहा है।



पिछले दस वर्षों के दौरान भारत विश्व की सबसे तेजी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। देश में बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, डिजिटल दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, और वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास को हासिल किया गया है

भारत और इटली आर्थिक साझेदारी को करेंगे मजबूत, निवेश और व्यापार बढ़ाने पर फोकस : पीयूष गोयल

नई दिल्ली.एजेंसी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि उनका मौजूदा रोम दौरा भारत और इटली के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा, नए निवेश अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा और दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के लिए सहयोग के नए द्वार खोलेगा। पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी यात्रा के अवसर पर 'रोम टू न्यू दिल्ली: बिल्डिंग ट्रस्ट, एंटीसिपेटिंग चेंज (रोम से नई दिल्ली: विश्वास कायम करना, बदलाव की उम्मीद करना)' शीर्षक से एक लेख लिखा है।

गोयल ने कहा कि यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के उस साझा विजन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके तहत दोनों देश



2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में गोयल ने कहा कि वह इटली के साथ भारत-इटली आर्थिक सहयोग संयुक्त आयोग की 23वीं बैठक और भारत-इटली बिजनेस फोरम के चौथे संस्करण की सह-अध्यक्षता करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हो चुका है और आगामी बैठकें निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग को नई गति देंगी।

राजनाथ ने जापान के नौसैनिक अड्डे का किया दौरा, युद्धपोत का भी किया निरीक्षण

जापानी नौसैनिक अड्डे व युद्धपोत का दौरा, भारत-जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी गर्मजोशी

नई दिल्ली.एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान की यात्रा पर हैं। बुधवार को उन्होंने जापानी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ विमान में सफर किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान से अपनी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के योकोसुका स्थित नौसैनिक अड्डे का दौरा करने की जानकारी दी। राजनाथ सिंह यहां जापान के मोगामी श्रेणी के युद्धपोत का दौरा भी कर रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोइजुमीह के टोक्यो स्थित रक्षा मंत्रालय पहुंचे। यहां पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने अपने जापानी



भारत-जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों के गहरे विश्वास और साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है : राजनाथ

समकक्ष की मेजबानी की भी तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा, मेरे जापानी समकक्ष एक बेहतरीन मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं।

राजनाथ 18 और 19 नवंबर को जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वह भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2 प्लस 2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। दोनों नेताओं की बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भी राजनाथ सिंह की यात्रा को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा था कि वह भारत के रक्षा मंत्री का जापान में स्वागत करने और उनके साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। कोइजुमी के मुताबिक, पिछले चार महीनों में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले अगस्त में भारत और अक्टूबर में फिलीपींस में दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच 2 प्लस 2 वार्ता भी हो रही है। कोइजुमी ने राजनाथ सिंह को अपने गृह नगर योकोसुका ले जाने और उनके साथ मोगामी श्रेणी के युद्धपोत का दौरा करने की इच्छा भी जताई।

बिहार कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर फैसले

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खनिज संपदा के दोहन, खाद्यान्न अधिप्राप्ति, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, पंचायत सरकार भवनों में सौर ऊर्जा, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कैबिनेट ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने



की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। किसानों के हित में वित्त वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक, इससे खरीद व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।

स्पेस ऑन व्हील से जनजातीय अंचलों के बच्चों तक पहुंच रहा अंतरिक्ष विज्ञान

बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगाने की पहल को मिला सीएम का प्रोत्साहन

ओपन सर्च. संवाददाता

रायपुर। जिन बच्चों के लिए उपग्रह अब तक आसमान में चमकते बिंदु भर थे, उनके सामने अब इसरो के उपग्रहों के मॉडल मौजूद हैं। विज्ञान को प्रयोगशालाओं और बड़े संस्थानों तक सीमित न रखकर गांवों और स्कूलों तक पहुंचाने में जुटी विज्ञान भारती की इस पहल की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सराहना की। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में विज्ञान भारती के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साय ने संस्था के प्रतिनिधियों से आत्मीय भेंट की। साथ ही उन्होंने जनजातीय अंचलों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के संस्था के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और नवाचार के प्रति जिज्ञासा नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए



विज्ञान को प्रयोगशालाओं और बड़े संस्थानों तक सीमित न रखकर गांवों और स्कूलों तक पहुंचाने में जुटी विज्ञान भारती की इस पहल की मुख्यमंत्री साय ने सराहना की

महत्वपूर्ण है। जनजातीय अंचलों के बच्चों को देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने से उनमें नई चीजों को जानने-समझने की रुचि बढ़ेगी और नई संभावनाओं के प्रति उत्सुकता विकसित होगी। संस्था के प्रतिनिधि वर प्रसाद कोला ने मुख्यमंत्री को विज्ञान भारती की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विज्ञान भारती राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्था स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य कर रही है। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ नई पीढ़ी के वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। इसरो, आईसीएमआर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का भी इसमें योगदान है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक

हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी नई गति

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद।

इनके अलावा, पर्यावरण एवं विशेष रूप से ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसी ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चार मुख्य क्रिटिकल क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं एनर्जी एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ हो। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग के माध्यम से धरातल पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए परियोजनाओं की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ प्रदेश को मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शून्य उत्सर्जन (नेट-ज़ीरो) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है।

सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब किसान पराली को जलाने के बजाय उसका सदुपयोग कर इसे आय के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना रहे हैं।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के महानिदेशक प्रभजोत सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा फ्यूचर विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की सरकार की पहल की सराहना, सहयोग और योगदान देने की जताई इच्छा

बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने फंड के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग एवं योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए 'पृथ्वी' नाम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 'पृथ्वी' कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि फंड के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिल सके।

NHAI से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जगमोहन आनंद ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र





गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से संबंधित करनाल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा करनाल के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर प्रमुख मांगें उठाई हैं। विधायक जगमोहन आनंद ने बताया कि ह्यात्ढ के अंतर्गत आने वाले जीटी रोड के करनाल क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं सामने आई हैं, जिनके कारण आमजन को रोजमर्रा के आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उनके प्रयास लगातार जारी हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इनका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सेक्टर-9 स्थित अटल पार्क के सामने एक बड़े व्हीकुलर अंडरपास का निर्माण करवाना तथा सेक्टर-12 के लिए स्लिप एग्जिट उपलब्ध करवाना शामिल है।

इन सुविधाओं के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी। विधायक ने कहा कि इससे पहले भी जनहित से जुड़े कई कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। सेक्टर-6 के पास मेरठ रोड के लिए एग्जिट का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नमस्ते चौक और मेरठ रोड के पास जलभराव की समस्या का भी समाधान करवाया गया है। वहीं, जीटी रोड के सेंटर वर्ज पर लगी खराब लाइटों को बदलवाकर नई लाइटें लगवाने और व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का कार्य भी जारी है। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जनहित एवं विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। करनाल के विकास और आमजन की सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सहयोग से NHAI से जुड़ी इन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी और करनाल वासियों को जल्द राहत मिलेगी।

गेहूं की बिजाई पिछड़ी, सिरसा और फतेहाबाद के किसानों को तत्काल नहरी पानी दे सरकार : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



सिरसा। सिरसा की कांग्रेस सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में गेहूं की बिजाई में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सिरसा और फतेहाबाद जिलों में नहरी पानी की आपूर्ति तत्काल बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल एक सप्ताह पानी मिलने से बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों की सिंचाई कर समय पर बिजाई नहीं कर पा रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में अब तक करीब 1.79 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई है। पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा करीब 4.44 लाख हेक्टेयर था। इस तरह गेहूं की बिजाई करीब 6.55 लाख एकड़ पीछे है। उन्होंने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद में सिंचाई के इंतजार में बैठे किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बिजाई में और देरी से पैदावार और किसानों की आमदनी प्रभावित होने की आशंका है। सांसद ने आरोप लगाया कि नहरी पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुनने और पानी उपलब्ध कराने की जगह सरकार उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर रही है। सांसद ने मांग की कि प्रशासन किसान प्रतिनिधियों से तत्काल बातचीत करे, दर्ज मामलों की समीक्षा कराए और बेबुनियाद पाए जाने वाले मामले वापस ले।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर चिकित्सा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो

करनाल। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग करनाल एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में सहज योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, नंबर 979, सेक्टर-9, कृष्ण धाम मंदिर के नजदीक में विशेष चिकित्सा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा के प्रतिनिधि कविन्द्र राणा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. राम अवतार सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम आयुष विभाग हरियाणा के महानिदेशक संजीव वर्मा के आदेशानुसार तथा उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा के दिशा-निर्देशन में आयुष विभाग, करनाल एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया



गया। कार्यक्रम में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, उनके महत्व, व्यावहारिक उपयोग एवं स्वास्थ्य संरक्षण में उनकी भूमिका पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारी प्राचीन एवं समृद्ध चिकित्सा परंपरा और प्राकृतिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने स्वस्थ समाज के निर्माण में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आमजन को प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञ एवं पंचकर्म केंद्र, सेक्टर-6, करनाल के डॉ. अमित पुंज ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व, वर्तमान समय में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इसकी उपयोगिता तथा विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के व्यावहारिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त डॉ. संदीप ने ठंडी एवं गर्म सिकाई, सूर्य चिकित्सा तथा बस्ती क्रिया के महत्व एवं उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। डॉ. दीपिका ने उपवास चिकित्सा, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा एवं मिट्टी चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, उनकी उपयोगिता एवं स्वास्थ्य संरक्षण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना तथा संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, योग एवं प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए 20 नवंबर से लाईव होंगे आवेदन फार्म

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा फरवरी/मार्च-2027 आयोजित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी मुक्त विद्यालय परीक्षा हेतु सी.टी.पी., ओ.सी.टी.पी., रि-अपीयर, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार एवं पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी के तहत आवेदन करने के इच्छुक परीक्षार्थी 20 नवंबर, 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) सी.टी.पी./ओ.सी.टी.पी./ अतिरिक्त विषय /रि-अपीयर/आंशिक व पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी की परीक्षा के लिए 1450 रूपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) सी.टी.पी./ओ.सी.टी.पी./ अतिरिक्त विषय /रि-अपीयर/आंशिक व पूर्ण विषय अंक सुधार की परीक्षा के लिए 1500 रूपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क 20 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रति विषय 100 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

उन्होंने बताया कि जो परीक्षार्थी उक्त निर्धारित तिथियों में आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे परीक्षार्थी 100/- रूपये विलंब शुल्क सहित 01 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, 300 विलंब शुल्क सहित 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक तथा 1000 रूपये विलंब शुल्क सहित 22 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सभी दिशा-निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा ने देश भर में हासिल किया प्रथम स्थान

ओपन सर्च ब्यूरो



- राष्ट्रीय औसत 66.2 के मुकाबले 89.2 एएमबी इंडेक्स के साथ राज्य ने रचा कीर्तिमान

- स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभागीय समन्वय और ठोस प्रयासों को दिया श्रेय

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा ने 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह बड़ी उपलब्धि सभी लाभार्थी समूहों में नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के आपसी समन्वय और ठोस प्रयासों का ही परिणाम है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के स्कोरकार्ड (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली-HMIS के अनुसार) में हरियाणा ने 'एनीमिया मुक्त हरियाणा / एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम के तहत आयरन और फोलिक एसिड कवरेज में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 89.2 का एएमबी इंडेक्स प्राप्त किया है, जो 66.2 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, और इस शीर्ष रैंक को हरियाणा ने उत्तराखंड के साथ साझा किया है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय एनीमिया मुक्त भारत और पोषण अभियान के तहत नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन, गहन जांच, समय पर उपचार, परामर्श तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर की गई मजबूत निगरानी के निरंतर प्रयासों को दिया। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन डायरेक्टर डॉ आर. एस ढिल्लों ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के 78.5% (तीसरे स्थान) के समग्र आईएफए कवरेज इंडेक्स को सुधारकर दूसरी तिमाही में 89.2% (पहले स्थान) तक पहुंचा दिया है।

इस दौरान सभी श्रेणियों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है, जिसमें 6 से 59 महीने के बच्चों का कवरेज 78.0% से बढ़कर 89.3 प्रतिशत, 5 से 9 वर्ष के बच्चों का कवरेज 77.0% से बढ़कर 80.5 प्रतिशत, 10 से 19 वर्ष के किशोरों का कवरेज 74.1% से बढ़कर 95.0% और स्तनपान कराने वाली माताओं का कवरेज 68.2% से बढ़कर 86.1% हो गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं का कवरेज 95.0% पर बरकरार रखा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के हिस्से के रूप में 17 सितंबर, 2026 को अंबाला से '100 दिवसीय एनीमिया न्यूनीकरण अभियान' की भी शुरुआत की गई थी। स्टेट एनीमिया ट्रैकिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 3.56 लाख से अधिक हीमोग्लोबिन टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि एक स्वस्थ और सशक्त हरियाणा का निर्माण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला में कचरा जलाने और अवैध भट्टियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : नेहा सिंह

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में खुले में कचरा जलाने, प्लास्टिक, रबड़, औद्योगिक अपशिष्ट जलाने तथा बिना वैध अनुमति के अवैध भट्टियों में धातु और स्क्रैप को गलाने एवं प्रोसेस करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ये आदेश 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुके हैं और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे, जब तक इन्हें पहले संशोधित या वापस नहीं लिया जाता। जिलाधीश नेहा सिंह ने बताया कि जिले के आवासीय, कृषि, गैर-अनुरूप तथा अन्य क्षेत्रों में नगर निकायों के ठोस कचरे, घरेलू कूड़े, पत्तों, प्लास्टिक, रबड़, औद्योगिक अपशिष्ट, पैकेजिंग सामग्री, कृषि अवशेष और अन्य प्रकार के कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा धातु स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, बिजली की केबल और मिश्रित स्क्रैप को खुले में आग लगाकर अथवा अस्थायी भट्टियों और मिट्टी की भट्टियों में गलाने या प्रोसेस करने की गतिविधियां भी बिना संबंधित विभागों की वैधानिक अनुमति के नहीं की जा सकेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, कबाड़ व्यापारी, औद्योगिक इकाई, ठेकेदार अथवा अन्य संस्थान अपने परिसर में ऐसी अवैध भट्टी स्थापित या संचालित नहीं कर सकेगा और न ही किसी अन्य को इसकी अनुमति देगा। परिसर का मालिक या कब्जाधारी भी अपने परिसर का इस प्रकार की प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।

जनगणना-2027 : सोनीपत में 25 जनवरी से शुरू होगी जनसंख्या गणना : डीसी नेहा सिंह

ओपन सर्च ब्यूरो



सोनीपत। हरियाणा राज्य में भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत 1 मार्च से 5 मार्च, 2027 तक पांच दिवसीय पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जनसंख्या गणना के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्कूल शिक्षकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना से पूर्व हरियाणा के नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान नागरिक https:// se.census.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना-2027 में जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। गणक स्मार्टफोन पर उपलब्ध निर्धारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे।

वहीं, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्य की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय एवं क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी को मजबूत बनाया जाएगा। डिजिटल व्यवस्था से आंकड़ों के संकलन में त्रुटियों को कम करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना के दौरान निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न शामिल होंगे। इनके माध्यम से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक गतिविधियों, भाषा, प्रवास तथा अन्य निर्धारित विषयों से संबंधित विवरण संकलित किए जाएंगे। इन आंकड़ों का उपयोग देश एवं प्रदेश में विकास योजनाओं के निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन तथा विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी जरूरतों को समझने में किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक परिवार एवं नागरिक की भागीदारी जनगणना को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

हरियाणा ने 31 दिसंबर तक सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के 'सुरक्षित जिला' ढांचे में लाने का लक्ष्य रखा

ओपन सर्च ब्यूरो



- एचआईवी की जांच कवरेज बढ़कर 94.7 प्रतिशत, एआरटी उपचार कवरेज 91.1 प्रतिशत और वायरल सप्रेशन 95.8 प्रतिशत पहुंचा

- उपचार बीच में छोड़ चुके 6,000 से अधिक मरीजों को तलाश कर दोबारा स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा

चंडीगढ़। हरियाणा ने 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए 'सुरक्षित जिला' (सुरक्षित जिला) के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला प्रशासन और कार्यक्रम अधिकारियों को जांच, उपचार तथा मरीजों की निगरानी से जुड़े प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा चंडीगढ़ में 'सुरक्षा संकल्प कार्यशाला' पहल के तहत आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है। जुलाई 2026 में एचआईवी जांच कवरेज 85.2 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, एचआईवी संक्रमित पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त करने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत हो गया है, जबकि वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित संपर्क से बाहर हो चुके 6,052 लोगों को तलाश कर दोबारा उपचार से जोड़ा गया है।

यह मरीजों की निगरानी और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत सहित सात जिले पहले ही 'सुरक्षित जिला' का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अब प्राथमिकता इस उपलब्धि को प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाने की है।

उन्होंने इन जिलों के उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कार्यक्रम से जुड़ी टीमों को बधाई दी तथा शेष जिलों को भी इसी दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मिशन मोड में कार्य करते हुए आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में शेष कमियों को दूर करें।

एचआईवी/एड्स के उपचार में आ रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के चलते अब एचआईवी को एक नियंत्रित की जा सकने वाली स्वास्थ्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इसके लिए समय पर जांच, बिना किसी रुकावट के नियमित उपचार और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी बेहद जरूरी है।

भारत-कुवैत के कूटनीतिक रिश्तों के 65 साल, मजबूत आर्थिक संबंधों के चलते द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजदूत अल-शेमाली ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते लगातार विस्तार कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनके और मजबूत होने की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कुवैत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया

भारत और कुवैत के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुवैत के राजदूत मेशाल अल-शेमाली ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत कुवैत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है।

भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजदूत अल-शेमाली ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते लगातार विस्तार कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनके और मजबूत होने की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कुवैत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कुवैत वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 5 प्रतिशत पूरा करता है। राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच अब तक लगभग 40 समझौते और सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इनमें राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, श्रम, नागर विमानन, खेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और गहरा बनाने के लिए कई नए समझौतों पर भी चर्चा चल रही है।

विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, निवेश और व्यापार सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में नई पहलें आने वाले समय में आगे बढ़ सकती हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को कुवैत दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए अल-शेमाली ने कहा कि कुवैत विजन 2035 और भारत के 'विकसित भारत 2047' विजन के बीच कई समानताएं हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक सहयोग को और विस्तारित करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

उन्होंने 65वीं वर्षगांठ को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारत और कुवैत के संबंध लंबे समय से मित्रता, पारस्परिक सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित रहे हैं। राजदूत ने यह भी याद दिलाया कि हालांकि दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे, लेकिन भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंध कई सदियों पुराने हैं। समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वाणिज्यिक संपर्कों ने दोनों समाजों को लंबे समय से जोड़े रखा है। कार्यक्रम के दौरान अल-शेमाली ने भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को भी सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंध, आपसी समझ और सहयोग इस साझेदारी की महत्वपूर्ण नींव हैं। समारोह में भारत के विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया मामलों के सचिव, राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि यह वर्षगांठ दोनों देशों के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने तथा नागरिकों के समृद्ध भविष्य के लिए साथ काम करने का अवसर है। सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुवैत दूतावास ने कुवैती अल-सदू हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन और भारत के कश्मीर लूम हाउस के सहयोग से तीन दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है।

यह 65वीं वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब कुवैत और भारत अपने ऐतिहासिक सद्भाव और स्थापित आर्थिक संबंधों को और गहरे रणनीतिक सहयोग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापक व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे पर निर्भरता, लगभग 40 द्विपक्षीय समझौतों और राष्ट्रीय विकास के पूरक दृष्टिकोणों के साथ इस साझेदारी में अपने पारंपरिक आधार से आगे विस्तार करने की काफी संभावनाएं हैं।

दिल्ली में प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने का आरोप- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आप, सीजेपी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाने वाली व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी , सीजेपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किया है। याचिका किराना कमेटी दिल्ली और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली में पिछले महीने हुए प्रदर्शनों के कारण सेंट्रल दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। व्यापारियों ने विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है।

व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान के आसपास भी कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां आयोजित होने वाले प्रदर्शनों और रैलियों से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा था। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी याचिका में संशोधन किया। बुधवार को संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि व्यापारियों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फिलहाल 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

भारत ने बनाई बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन, शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे लॉन्च

नई दिल्ली (एजेंसी)



केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को मुर्गियों के लिए भारत की पहली देसी 'इनएक्टिवेटेड एच5एन1' एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। आईसीएआर-एनआईएचएसएडी भोपाल ने मुर्गियों के लिए पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन से देश में फैल रहे 'क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1' वायरस के स्ट्रेन से सुरक्षा मिलेगी। अभी, क्लेड 2.3.2.1ए के एच5एन1 वायरस के खिलाफ कोई खास कमर्शियल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए, भारत के लिए एक देसी वैक्सीन बनाना जरूरी है। बहुत ज्यादा पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई), जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, पोल्ट्री को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसके फैलने से इंफेक्टेड पक्षियों में लगभग 100 प्रतिशत मौत हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारने और व्यापार पर रोक लगने के कारण पोल्ट्री फॉर्मरों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।

इसका असर सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक ही नहीं है; यह वैश्विक व्यापार, पोल्ट्री उत्पाद की कीमतों और पोल्ट्री फॉर्मरों की रोजी-रोटी पर भी असर डाल सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 2006 में भारत में इस बीमारी का पहली बार पता चलने के बाद से, देश में एच5एन1 और एच5एन8 सबटाइप के 500 से ज्यादा मिले-जुले मामले सामने आए हैं। बर्ड फ्लू का एक बड़ा प्रकोप भारत की जीडीपी ग्रोथ को 1.5 प्रतिशत तक कम कर सकता है जबकि अगर यह बीमारी बिना कंट्रोल के फैलती है तो देश की 20 प्रतिशत से ज्यादा पोल्ट्री आबादी खतरे में पड़ सकती है। 2006 में बर्ड फ्लू के प्रकोप से लगभग 2,200-3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मणिपुर में भी इसके प्रकोप से राज्य की जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर नुकसान हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2003 से भारत समेत 25 देशों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा के 1,003 इंसानों में मामले सामने आए हैं, जिनमें 479 मौतें शामिल हैं। स्टडीज से पता चला है कि क्लेड 2.3.2.1ए नाम का एच5एन1 स्ट्रेन मुर्गियों में बर्ड फ्लू के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार है। बयान में कहा गया है कि इससे पोल्ट्री फॉर्मरों के पैसे के नुकसान को कम करने और मुर्गियों से दूसरे जानवरों और इंसानों में इसके फैलने को रोकने के लिए इस वायरस के फैलने को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाली एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत के समक्ष यह मामला रखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अंतरिम राहत की मांग करते हुए एएसजी राजू ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से 'यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई तात्कालिक स्थिति नहीं है, जिसके कारण खान को दी गई अंतरिम जमानत में दखल देने की जरूरत पड़े। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। यह घटनाक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खान को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत दर्ज मामले में 10 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है।

चाहे जितना दम लगा लें, सरकार को राहुल गांधी हिला भी नहीं पाएंगे : गौरव भाटिया

नई दिल्ली (एजेंसी)



भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने कहा, 'अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की ओर से देश को बदनाम करने वाला बयान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। चाहे लोकतंत्र की आंतरिक ताकत, अर्थव्यवस्था, युवा, विश्व पटल पर भारत की साख की बात हो, बिल्कुल स्पष्टता से इसको लेकर बात करूंगा। हम लोग बार-बार दिखाते हैं कि कैसे अराजकता के प्रतीक, देश से नफरत करने वाले राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो उनकी ओर से झूठे बयान दिए जाते हैं।' उन्होंने कहा, राहुल गांधी की एक ही मंशा होती है कि देश की प्रगति पर ठेस लगे। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, यह हर किसी को पता है। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष होते हुए राहुल गांधी विदेशी धरती पर जहरीले बोल बोलते हैं तो इससे समझ आता है कि वे भारत विरोधी हैं। संसद सत्र होने से पहले राहुल गांधी विदेशी धरती पर जरूर जाते हैं। क्या वे अपने विदेशी आकाओं से मार्गदर्शन लेने जाते हैं? देश में 12 वर्ष से एक स्थिर सरकार है, वे चाहते हैं कि स्थिरता नष्ट हो जाए।

गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, जिनको लगता है कि देश आर्थिक आपदा पर बैठा है। यूपीए सरकार के तीन अवगुण थे। महंगाई डबल डिजिट में बढ़ती थी। नीतिगत फैसले लेने में लकवा मार जाता था। फाइलों का निपटारा तब तक नहीं होता था, जब तक कि रिश्वत नहीं मिल जाती थी। यूपीए के शासनकाल में टूजी, कोलगेट, सीडब्ल्यूजी जैसे घोटाले ही घोटाले होते थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा है, इसके संदर्भ को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। देश का भी भविष्य उज्ज्वल है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनौतियों को हराकर भारत के लिए उज्ज्वल भविष्य गढ़ना ही हमारा मकसद और प्रतिबद्धता है। 2047 तक विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने अपने लिए निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी झुठ बोलते हैं और देश को बदनाम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर वे चोट करते हैं। ये सभी आराकता की टूल किट हैं। जितना दम हो राहुल गांधी लगा लें, देश का लोकतंत्र मजबूत है।

एनसीआर में पारा गिरा, वायु गुणवत्ता में सुधार से मिली राहत

पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है

नई दिल्ली (एजेंसी)



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखें तो 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन औसतन तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 18 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 19 नवंबर को अधिकतम तापमान गिरकर 26 डिग्री पर आ जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री बना रहेगा। 20 नवंबर को दिन का तापमान और गिरेगा, जो 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री रहने का अनुमान है।

21 नवंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 22 नवंबर और 23 नवंबर को महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है। यानी साफ है कि दिन में धूप निकलने के बावजूद तापमान 24-25 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है, जिससे दिन में भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं रातें काफी ठंडी हो चुकी हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक लगातार 'मॉडरेट फॉग' यानी मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहने की बात कही गई है। हवा में नमी की मात्रा भी काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, सुबह के समय आर्द्रता 90 से 95 प्रतिशत तक पहुंच रही है, जबकि दोपहर में यह 65 से 75 प्रतिशत के बीच रह रही है। इस उच्च आर्द्रता और ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। ठंड बढ़ने के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर के लिए एक अच्छी खबर भी है। तेज हवाओं के चलने से प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हवा की गति बढ़ने से वातावरण में फैले प्रदूषक कण बिखर गए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में तेजी से गिरावट आई है।

पहले जहां एक्यूआई 'सीवियर' या 'बहुत खराब' श्रेणी में था, अब वह सुधरकर 'येलो' (मध्यम) और 'ऑरेंज' (खराब) जोन में पहुंच गया है। यह अपने आप में एनसीआर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब सांस लेने में पहले जैसी परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास करा दिया है।

'लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा', अमेरिका में राहुल गांधी के बयान की भाजपा ने की आलोचना

नई दिल्ली (एजेंसी)



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश एक 'आर्थिक आपदा' की ओर बढ़ रहा है तथा बड़ी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार सृजन और शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं देश के विकास के सामने बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

राहुल गांधी के बयानों की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के दो दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यह बात कही। वहां वे मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन द्वारा भारत के युवाओं से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान कहा, सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है। यही हकीकत है।

आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, मीडिया इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर निराशा जताने वाले कुछ युवा मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं और उन्होंने औपचारिक शिक्षा भी हासिल की है। युवाओं के बीच बढ़ती निराशा का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपना भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आ रहा है। इसी बातचीत के दौरान, गांधी ने अपने 'वोट चोरी' वाले आरोपों को फिर दोहराया और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 140 मिलियन (14 करोड़) लोग, जो 2024 में वोट दे सकते थे, उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, इन हालात में चुनाव को वैध कैसे माना जा सकता है? फिर भी, वे इस पर चुप हैं। चुनावी व्यवस्था में सुधार किए बिना कुछ नहीं होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास चुनावी धांधली के पुख्ता सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, सिस्टम के भीतर के लोग डर के कारण हमसे बात कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर दबाव एक हद से ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार इसके जवाब में हिंसा का सहारा ले सकती है।

पहले डर का माहौल था, लेकिन अब लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इसमें छात्र आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 'एक्स' पर लिखा, राहुल गांधी भारत-विरोधी प्रचार (लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा) के नेता बन गए हैं।

दीपक राजावत एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए CEO बने, एक दिसंबर से संभालेंगे कमान

नई दिल्ली (एजेंसी)



एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) दीपक राजावत को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगी। राजावत एयरलाइन के वित्त विभाग का नेतृत्व करने और एयर इंडिया समूह के भीतर तेजी से विस्तार के दौर में इसकी विकास एवं बदलाव संबंधी पहलों में योगदान देने के बाद शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एयरलाइन ने कहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस के निदेशक मंडल ने आज दीपक राजावत को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगी। एयरलाइन ने आगे कहा, वर्तमान में एयरलाइन के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत दीपक, कंपनी के वित्त विभाग का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने और एयरलाइन की विकास एवं बदलाव की यात्रा में योगदान देने के बाद इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विमानन और वित्त क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राजावत एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्हें वित्तीय प्रबंधन, वाणिज्यिक परिचालन और रणनीतिक योजना के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में सीएफओ के रूप में शामिल होने के बाद से उन्होंने एयरलाइन की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ इसके विस्तार और एकीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहले राजावत विमानन कंपनी विस्तारा की शुरुआत से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने कॉरपोरेट योजना, विमान अधिग्रहण और वित्त सहित कई क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों पर काम किया। बाद में उन्होंने विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रबंधन, नेटवर्क योजना, बिक्री एवं वितरण, गठजोड़ एवं साझेदारी, उत्पाद विकास, उड़ान के दौरान दी जाने वाली सेवाओं, विपणन, ब्रांडिंग और ग्राहक अनुभव जैसे क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाली।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ईवी को बढ़ावा, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था : मंत्री पंकज कुमार सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाए जाने के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

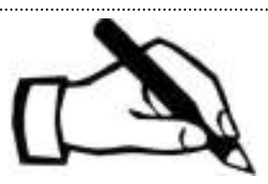
इसके अलावा, सरकार ने सरकारी अस्पतालों को भी सांस संबंधी बीमारियों से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान काफी अच्छा है। सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोग ईवी नीति को अपनाएं और अपने निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलें। कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में आगे भी कदम उठाएगी।

दिल्ली की बसों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। बसों को ईवी में बदलना सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य है और दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में आगे बढ़ाना प्राथमिकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पीयूसी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए एक लाख रुपए का अनुदान दिया है। संबंधित लोगों से व्यवस्था को अपडेट करने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में समयसीमा तय करने पर भी काम किया जाएगा, ताकि पीयूसी के माध्यम से वाहनों की जांच बेहतर तरीके से हो सके। वाहनों की नियमित जांच और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों से दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की अस्पतालों में बढ़ती जरूरतों को लेकर पूछे गए सवाल पर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहता है। अक्टूबर से ही अस्पतालों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए थे। सभी जगह बेड, डॉक्टर और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सांस लेने में परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को नेबुलाइजेशन और राहत देने वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए पर्याप्त दवाएं और बेड अस्पतालों में उपलब्ध हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता, विशेषकर महिलाओं और परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी।

सम्पादकीय



बदलती अर्थव्यवस्था, नए भारत की नई उड़ान

भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है। वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए अनेक नीतिगत पहल कीं। इनका उद्देश्य देश को मजबूत आर्थिक शक्ति बनाना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना रहा है। मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल का आधार विकास, निवेश, आत्मनिर्भरता, तकनीकी बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना है।

इस आर्थिक मॉडल की एक प्रमुख विशेषता बुनियादी ढांचे पर बढ़ता निवेश है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली और शहरी विकास जैसी परियोजनाओं को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, वंदे भारत ट्रेनें, रेलवे का विद्युतीकरण, माल ढुलाई गलियारों का विकास और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में सुधार जैसे कदमों का उद्देश्य परिवहन लागत कम करना और व्यापारिक गतिविधियों को गति देना है। सरकार का मानना है कि मजबूत आधारभूत ढांचा निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।

'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाएं इस आर्थिक सोच के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और औषधि उद्योग जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। इसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को वैश्विक उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। हालांकि, इस दिशा में निरंतर प्रगति के लिए तकनीकी अनुसंधान, कुशल श्रमशक्ति, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और छोटे उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना भी जरूरी है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भी भारत के आर्थिक ढांचे को नया स्वरूप दिया है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल आधारित सेवाओं के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित हुई है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आम नागरिकों, छोटे दुकानदारों और कारोबारियों तक पहुंचाया है। डिजिटल लेनदेन की बढ़ती स्वीकार्यता ने वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार किया है। इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। सरकार के आर्थिक मॉडल में गरीबों और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है।

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था

डॉ. प्रियंका 'सौरभ'

डिजिटल क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और नागरिक जीवन को नई गति दी है। आज मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे भेजना, बिलों का भुगतान करना, खरीदारी करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट ने वित्तीय लेन-देन को आम आदमी की पहुँच में ला दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक गंभीर चुनौती भी तेजी से उभरी है–साइबर धोखाधड़ी। तकनीक ने जहाँ आर्थिक गतिविधियों को सरल बनाया है, वहीं अपराधियों को लोगों की मेहनत की कमाई तक पहुँचने के नए रास्ते भी उपलब्ध कराए हैं। आज साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विश्वास और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के पीछे कई परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार और उसके अनुपात में डिजिटल साक्षरता का विकास न हो पाना है। देश के छोटे कस्बों, गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई की पहुँच तो बढ़ी है, लेकिन बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता डिजिटल सुरक्षा के बुनियादी नियमों से परिचित नहीं हैं। वे अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ओटीपी साझा कर देते हैं अथवा फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों के झाँसे में आ जाते हैं। अपराधी इसी जानकारी की कमी का लाभ उठाकर बैंक खातों से धन निकाल लेते हैं।

साइबर अपराध का एक खतरनाक स्वरूप फिशिंग और पहचान की धोखाधड़ी है। इसमें अपराधी बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान का प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे खाते केवाईसी अपडेट करने, बैंक खाता बंद होने, पार्सल में प्रतिबंधित वस्तु मिलने या किसी सरकारी जाँच का हवाला देकर भय और भ्रम पैदा करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी इसका सबसे चिंताजनक उदाहरण है। इसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जाँच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को मानसिक रूप से बंधक बना लेते हैं। गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपये तक वसूल लिए जाते हैं।

तकनीक के दुरुपयोग ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की सहायता से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और नकली आवाजें अब किसी व्यक्ति की पहचान की नकल करने में सक्षम हैं। अपराधी रिश्तेदार, परिचित, वरिष्ठ अधिकारी अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवाज में फोन करके आपातकालीन आर्थिक सहायता माँग सकते हैं। पहले जहाँ गलत वर्तनी वाले संदेशों और संदिग्ध ईमेल से धोखाधड़ी की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब अत्याधुनिक तकनीक ने अपराधियों के छल को अधिक विश्वसनीय बना दिया है। एक अन्य बड़ी समस्या म्यूल बैंक खातों की है। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कई बार बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मामलों में लोग बिना पूरी जानकारी के अपने खाते और एटीएम कार्ड दूसरों को सौंप देते हैं। अपराधी इन खातों की श्रृंखला बनाकर धन की वास्तविक पहचान और स्रोत छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क, फर्जी सिम कार्ड, नकली पहचान और सीमापार डिजिटल लेन-देन के कारण जाँच एजेंसियों के सामने भी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।



दिलचस्प बात यह है कि साइबर धोखाधड़ी केवल अपराधियों की चालाकी का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार संस्थागत कमजोरियाँ भी इसे बढ़ावा देती हैं। बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल ग्राहकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती। बैंकों को संदिग्ध खातों की पहचान, मजबूत केवाईसी प्रक्रिया और असामान्य लेन-देन की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। यदि किसी खाते में अचानक बड़ी मात्रा में धन आने-जाने लगे अथवा कम समय में कई संदिग्ध लेन-देन हों, तो बैंक की निगरानी प्रणाली को तत्काल सक्रिय होना चाहिए। विशेष रूप से म्यूल खातों की पहचान के लिए बैंकों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियामक संस्था के रूप में आरबीआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा के कठोर मानक सुनिश्चित करने चाहिए। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, शिकायतों के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा की नियमित समीक्षा आवश्यक है। बैंकिंग संस्थानों को यह समझना होगा कि ग्राहक का विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूँजी है। यदि डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा का भरोसा कमजोर पड़ता है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

बैंकों के साथ-साथ दूरसंचार कंपनियों की जवाबदेही भी कम नहीं है। साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड, स्पूफ्ड कॉल और नकली मोबाइल नंबरों का उपयोग करके लोगों को निशाना बनाते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध सिम कार्डों की पहचान, फर्जी कनेक्शन पर रोक और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार की संचार साथी पहल इस दिशा में उपयोगी कदम है। इसके माध्यम से नागरिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन और मोबाइल फोन से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी पहलों का लाभ तभी व्यापक होगा, जब आम नागरिकों को इनके उपयोग की जानकारी भी हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी निर्णायक है। साइबर अपराध की प्रकृति ऐसी है कि अपराधी एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को निशाना बना सकता है और धन को तीसरे राज्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकता है।

इसलिए केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), साइबर अपराध पुलिस थानों और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। शिकायत दर्ज होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण, संदिग्ध खातों की पहचान और धन के प्रवाह का पता लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी पीड़ित की आर्थिक क्षति बढ़ा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। फर्जी विज्ञापनों, नकली निवेश योजनाओं, सरकारी अधिकारियों के नाम से बनाए गए खातों और भ्रामक लिंक के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार होते हैं।

बचपन की सुरक्षा, समाज की सर्वोच्च जिम्मेदारी

सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

बचपन जीवन का वह अनमोल समय है, जब बच्चे को स्नेह, सुरक्षा, शिक्षा और अच्छे संस्कारों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उसका संसार विश्वास, जिज्ञासा और सपनों से बनता है। लेकिन जब इसी उम्र में किसी बच्चे को शोषण, दुर्व्यवहार या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो उसकी मासूमियत ही नहीं, उसके आत्मविश्वास और भविष्य पर भी गहरा आघात पहुंचता है। किसी बच्चे के साथ होने वाला अन्याय केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता और व्यवस्था के सामने खड़ा गंभीर प्रश्न है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में 18 नवंबर को 'बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम तथा उससे उबरने के लिए विश्व दिवस' के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण और हिंसा को रोकना, पीड़ितों को न्याय तथा सहायता उपलब्ध कराना और उनके सम्मान, अधिकारों एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक दायित्व भी है। बच्चों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार अनेक रूपों में सामने आ सकता है। शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण, उपेक्षा, धमकी और डिजिटल माध्यमों से शोषण इसके गंभीर उदाहरण हैं। कई बार बच्चे भय, शर्म, भ्रम या किसी परिचित व्यक्ति के दबाव के कारण अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाते। इसलिए यह मान लेना गलत है कि बच्चा चुप है तो उसके साथ सब कुछ ठीक है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार में अचानक आए बदलाव, असामान्य भय, किसी व्यक्ति से मिलने में घबराहट अथवा लगातार उदासी जैसे संकेतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

ऐसे संकेत अपने आप में शोषण का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले, जहां वे बिना डरे अपनी बात कह सकें। यदि कोई बच्चा अपने साथ हुई किसी अनुचित घटना के बारे में बताता है, तो उसे डांटना, दोष देना या उसकी बात पर तुरंत अविश्वास करना उसके दर्द को और बढ़ा सकता है। उसकी बात शांतिपूर्वक सुनना, उसे यह विश्वास दिलाना कि उसकी गलती नहीं है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पहला कदम होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। उन्हें उम्र के अनुरूप यह समझाना चाहिए कि उनके शरीर और निजी सीमाओं का सम्मान आवश्यक है, वे किसी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और असहज स्थिति में भरोसेमंद वयस्क से सहायता मांग सकते हैं। बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि उन्हें डराकर, लालच देकर या गोपनीयता के नाम पर परेशान करे, तो वे इसकी जानकारी अभिभावक अथवा किसी विश्वसनीय शिक्षक को दें। विद्यालयों में बाल-सुरक्षा संबंधी स्पष्ट व्यवस्था, संवेदनशील शिकायत प्रक्रिया, प्रशिक्षित कर्मचारी और नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

बच्चों की शिकायतों को हल्के में लेना या प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें दबाना समस्या को और गंभीर बना सकता है। संस्थानों का पहला दायित्व बच्चे की सुरक्षा है, न कि अपनी छवि की रक्षा।डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। बच्चों को अनजान लोगों से निजी जानकारी साझा न करने, अनुचित संदेशों या तस्वीरों के दबाव में न आने और किसी संदिग्ध ऑनलाइन संपर्क की जानकारी भरोसेमंद वयस्क को देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिभावकों को निगरानी के साथ संवाद और विश्वास का वातावरण भी बनाए रखना होगा। भारत में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो कानून)' बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा मानता है और ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग तथा बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान करता है।

संबंधित मामलों में कानून के अनुसार सूचना देना और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शोषण का संदेह होने पर पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई जैसे सक्षम तंत्रों से सहायता ली जा सकती है। तत्काल खतरे की स्थिति में पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 से संपर्क किया जा सकता है। बच्चों की पहचान, निजी जानकारी और पीड़ा से जुड़ी सामग्री को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए, ताकि उनकी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे।

न्याय की प्रक्रिया के साथ मानसिक और भावनात्मक उपचार भी आवश्यक है। पीड़ित बच्चे को चिकित्सकीय सहायता, परामर्श, सुरक्षित वातावरण और परिवार के सहयोग की जरूरत हो सकती है। उसके साथ धैर्य और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। उसे बार-बार घटना बताने के लिए बाध्य करना या समाज के सामने उसकी पहचान उजागर करना उसके लिए अतिरिक्त पीड़ा का कारण बन सकता है।

बच्चों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए केवल एक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। परिवार, विद्यालय, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर निरंतर प्रयास करने होंगे। शिकायतों को गंभीरता से लेना, बच्चों को अधिकारों की जानकारी देना, दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना और पीड़ितों के पुनर्वास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बचपन को सुरक्षित रखना किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जिस समाज में बच्चे निर्भय होकर जी सकें, अपनी बात कह सकें और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सकें, वही समाज वास्तव में सभ्य और प्रगतिशील कहलाने का अधिकारी है। इस दिवस पर संकल्प लें कि बच्चों की आवाज सुनेंगे, उनकी सुरक्षा से जुड़े संकेतों को अनदेखा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जिम्मेदारी से कदम उठाएँगे।

घर भी, नौकरी भी : महिला कैसे बनाए संतुलन?

डॉ. विजय गर्ग

आज की महिला शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, व्यापार, स्वास्थ्य, खेल और अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रमाण दे रही है। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है और परिवार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। लेकिन इस सफलता के साथ उसके सामने एक बड़ी चुनौती भी है–घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखना। कामकाजी महिला के लिए सुबह से रात तक का समय अक्सर जिम्मेदारियों से भरा होता है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जरूरतें, कार्यालय का काम और सामाजिक जिम्मेदारियां उसके समय और ऊर्जा की मांग करती हैं। कई बार वह अपनी इच्छाओं, स्वास्थ्य और आराम को भी पीछे छोड़ देती है।

समय का सही प्रबंधन जरूरी

घर और नौकरी के बीच तालमेल बनाने के लिए समय की सही योजना बहुत जरूरी है। दिनभर के कामों की सूची बनाना, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना और अनावश्यक कामों से बचना लाभदायक हो सकता है। हर काम स्वयं करने के बजाय कुछ जिम्मेदारियां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करनी चाहिए।

परिवार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण

घर की जिम्मेदारी केवल महिला की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की साझा जिम्मेदारी है। पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को घरेलू कार्यों में भाग लेना चाहिए। जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, तो महिला का बोझ कम होता है और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं।

काम और निजी जीवन के बीच सीमा बनाएं

कार्यालय का काम घर लाने और हर समय मोबाइल या ईमेल से जुड़े रहने की आदत से बचना चाहिए। काम के समय काम और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय में परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुष्टि बढ़ती है।

अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें

कई कामकाजी महिलाएं परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पातीं। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकालना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की आवश्यकता है।

कार्यस्थल पर भी मिले सहयोग

संस्थाओं और सरकार को भी कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को समझना चाहिए। लचीले कार्य घंटे, माता-पिता के लिए छुट्टियां, सुरक्षित कार्यस्थल, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं और समान अवसर महिलाओं को अपना करियर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

पूर्णता नहीं, संतुलन जरूरी

महिला को यह समझना चाहिए कि हर दिन हर काम पूरी तरह करना संभव नहीं होता। कई बार कुछ काम अगले दिन के लिए छोड़ देना भी उचित है। स्वयं से असंभव अपेक्षाएं रखने के बजाय अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार काम करना चाहिए। वास्तव में घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाना केवल महिला की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए परिवार, समाज, कार्यस्थल और सरकार सभी का सहयोग आवश्यक है। महिला को केवल हर जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन समझने के बजाय उसकी भावनाओं, सपनों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।

सावधानियां

इंसान की छोटी सी गलती आगे चलकर
बहुत बड़ा उसे नुकसान कर सकती है।
इसलिए इंसान को हमेशा काम करते
समय कुछ सावधानियां को ध्यान में रखना
जरूरी है सावधानियों का मतलब यह नहीं है,
कि हम किसी भी काम को करने से बचें
सावधानियों का मतलब है कि कोई भी काम
करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए।



करिश्मा गुज्जर
(खारी)

प्रदूषण पर सुप्रीम की राज्य सरकारों पर लाल आंख

कांतिलाल मांडोत

प्रदूषण आज देश के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है। यह समस्या केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से फैल रही है। कहीं नदियां दूषित हो रही हैं तो कहीं हवा में घुलता जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं और समय-समय पर बड़े-बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। इसका ताजा उदाहरण यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

यमुना नदी भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। करोड़ों लोगों का जीवन किसी न किसी रूप में इस नदी से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद नदी में लगातार गंदे नालों, घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का पानी पहुंच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की हालत में सुधार नहीं होना प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। नदी में गिरने वाले लगभग 520 नाले इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। सवाल यह है कि जब सरकारों को प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी है, तब उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि यमुना नदी के प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले में प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए। नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है, वहां पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया जाए। यह निर्देश केवल यमुना की सफाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

न्यायालय ने यमुना एक्शन प्लान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। योजना में दिल्ली के जोन ओ के 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के दस्तावेजों में उन्हीं स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज होने की जानकारी सामने आई। ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट बताती है कि सरकारी योजनाओं और वास्तविक परिस्थितियों के बीच कितना अंतर है। यदि कागजों में नदी साफ दिखाई दे और जमीन पर उसमें गंदगी बहती रहे तो ऐसी योजनाओं का आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? प्रदूषण नियंत्रण के लिए न्यायालय ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इन संयंत्रों में छेड़छाड़ रहित स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने की व्यवस्था से उनकी वास्तविक कार्यप्रणाली पर नजर रखी जा सकेगी। केवल संयंत्र स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वे नियमित रूप से काम करें और निर्धारित मानकों के अनुसार गंदे पानी का शोधन करें। कई बार सरकारी धन से संयंत्र बन तो जाते हैं, लेकिन रखरखाव और निगरानी के अभाव में उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।

प्रदूषण की समस्या केवल नदियों तक सीमित नहीं है। देश के अनेक शहरों में वायु प्रदूषण भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसें, निर्माण कार्यों की धूल और कचरा जलाने की प्रवृत्ति वातावरण को दूषित कर रही है। इसका सीधा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी कोई विलासिता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

इस दिशा में सरकारों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके बसों, रेल और अन्य सार्वजनिक साधनों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में कार साझा करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक और कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देना भी समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही पैदल चलने और साइकिल के लिए सुरक्षित मार्ग विकसित किए जाने चाहिए।

पेड़-पौधे पर्यावरण के प्राकृतिक रक्षक हैं। शहरों में लगातार घटते हरित क्षेत्र और पेड़ों की कटाई ने भी प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाया है। इसलिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के साथ लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा। केवल पौधे लगाकर तस्वीरें खिंचवाना पर्यावरण संरक्षण नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करके उन्हें पेड़ बनाना वास्तविक जिम्मेदारी है।

औद्योगिक इकाइयों पर भी सख्त नियंत्रण जरूरी है। कारखानों की चिमनियों में आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और फिल्टर लगाए जाएं। औद्योगिक अपशिष्ट को बिना शोधन के नदियों या खुले जलस्रोतों में छोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शहरों में कूड़ा, प्लास्टिक और सूखे पत्ते जलाने पर रोक का प्रभावी पालन कराया जाए। नगरपालिकाओं को कचरा संग्रहण और निस्तारण की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे खुले में कचरा जलाने की नौबत ही न आए।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोग नदियों में कचरा न डालें, पानी की बर्बादी रोकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में भी पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सरकारों के लिए चेतावनी है कि पर्यावरण संरक्षण केवल घोषणाओं और बजट खर्च करने से संभव नहीं होगा। इसके लिए ईमानदार इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, नियमित निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। विकास की दौड़ में प्रकृति की उपेक्षा करना भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। नदियां स्वच्छ रहेंगी, हवा शुद्ध होगी और हरियाली सुरक्षित रहेगी तभी स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकेगी। अब समय आ गया है कि सरकारें कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर जमीन पर परिणाम दिखाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का खामियाजा अंततः पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

बिहार : 'नीतीश सेतु' नामकरण पर सियासत तेज, 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

पटना (एजेंसी)



उद्घाटन से पहले इस पुल के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है। बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देते हुए पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

बिहार में गंगा नदी पर बना एक और भव्य पुल राज्य की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक निर्मित छह लेन का 'नीतीश सेतु' बनकर तैयार हो गया है। करीब 5,571 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल को 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही राजधानी पटना पर यातायात का दबाव कम होने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, उद्घाटन से पहले इस पुल के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देते हुए पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नामकरण पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पुल के शिलान्यास के समय इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर सहमति जताई थी। तेजस्वी ने सरकार के मौजूदा फैसले पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद के नाम पर पुल का नामकरण करने की मांग उठाई है।

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखे जाने का समर्थन किया है। दरअसल, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में की गई थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) से इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष पुल के एलाइनमेंट और निर्माण की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण लेने की सिफारिश की। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला। जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया गया।

इस छह लेन के पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल के तहत किया गया है। परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ रुपये है। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया है। बताया गया कि नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा।

महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से राजधानी आने-जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी और यात्रा का समय तथा ईंधन दोनों बचेंगे। इसका लाभ कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी मिलेगा। उत्तर बिहार के लीची, केला, मक्का और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों को पटना और अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा। वहीं, कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं।

बिहार में भीषण सड़क हादसा : ट्रक-टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर में एक ही गांव के तीन युवकों की मौत

कटिहार (एजेंसी)

बिहार के कटिहार जिले में बुधवार अहले सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। पोठिया थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर बखरी मोड़ के पास ट्रक, टेम्पो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही गांव के तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।



घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पोठिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विष्णुचक गांव निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू (22), भीम कुमार साह (35) और बाजो कुमार साह (32) के रूप में हुई है। जितेंद्र कुमार के पिता का नाम स्वर्गीय गोपाल साह, भीम कुमार के पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र साह और बाजो कुमार के पिता का नाम स्वर्गीय महंत साह बताया गया है। वहीं, हादसे में घायल युवक की पहचान मनीष कुमार साह (24) के रूप में हुई है। उनके पिता का नाम अरविंद साह है। घायल को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पोठिया थाना के अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार, एसआई श्रीराम सिंह, एसआई राधेश्याम कुमार सहित बिहार पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद रहकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। चारों युवक कटिहार जिले के समेली प्रखंड के पोठिया थाना क्षेत्र स्थित विष्णुचक गांव के वार्ड संख्या-9 के रहने वाले हैं। एक ही गांव के तीन युवकों की असामयिक मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

बिहार : प्रसव के बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़

बक्सर (एजेंसी)



बिहार के बक्सर में मंगलवार रात प्रसव के बाद एक महिला की मौत से जमकर हंगामा हुआ। शहर के बाइपास रोड स्थित ताराचंडी अस्पताल में महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और महिला के शव के साथ सड़क जाम कर दिया। वे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के नरही थाना क्षेत्र के नसीरपुर मठ निवासी ओम प्रकाश यादव की पत्नी नीतू देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को नीतू देवी को प्रसव के लिए बक्सर के ताराचंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में उनका सामान्य प्रसव कराया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने महिला और नवजात दोनों की हालत सामान्य बताते हुए शाम करीब पांच बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी।

परिजन नवजात के साथ नीतू देवी को लेकर घर जाने के लिए निकले ही थे कि अस्पताल से कुछ दूरी आगे बढ़ने पर उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर दोबारा ताराचंडी अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि ताराचंडी अस्पताल में दोबारा जांच करने के बाद डॉक्टर ने महिला को सदर अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। इसके बाद परिजन आनन-फानन में नीतू देवी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वे वापस ताराचंडी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की गई। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने महिला के शव के साथ सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। मृतका के भतीजे अजीत यादव ने बताया कि गांव की आशा कार्यकर्ता के माध्यम से नीतू देवी को ताराचंडी अस्पताल लाया गया था। शुरुआत में डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराने की बात कही थी। इस पर परिजनों ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऑपरेशन करना है तो वे महिला को सदर अस्पताल ले जाएंगे।

प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़, एसपी ने मौके पर पहुंचकर कराया शांत

पूर्णिया (एजेंसी)



पूर्णिया शहर के मेडिकल हब लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज रोड पर एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान अमौर थाना क्षेत्र के मंगलपुर निवासी अनमोल यादव की पत्नी प्रियांशी यादव के रूप में हुई है। एक वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। प्रियांशी की मौत की खबर फैलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। साथ ही महिला का शव तीन घंटे तक मुख्य सड़क पर रखकर बिहारी टॉकीज रोड को जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा, सदर एसडीपीओ प्रभारी, के.हाट थाना, फणीश्वरनाथ टीओपी और सहायक खजांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने-बुझाने के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और जाम हटाया गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए उसे घर ले गए। मृतका के पति अनमोल यादव ने बताया कि मंगलवार शाम प्रसव पीड़ा उठने पर वे पत्नी को डॉ. सुस्मिता प्रसाद के अस्पताल में लाए थे। डॉक्टरों ने सुरक्षित डिलीवरी के नाम पर उन्हें भर्ती कर 51 हजार रुपये वसूल लिए। ऑपरेशन के बाद प्रियांशी ने एक बेटे को जन्म दिया और शुरुआत में वह ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने ब्लड चढ़ाने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने किसी तरह ब्लड की व्यवस्था की, लेकिन उसे चढ़ाया जा सके, इससे पहले ही प्रियांशी की मौत हो गई।

छठ महापर्व में मल्लिक समाज की अहम भूमिका, मूर्ति विसर्जन पर 300 लोगों का सम्मान

पटना (एजेंसी)



पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस घाट पर मल्लिक समाज की ओर से पहली बार भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई। मंगलवार को प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने मल्लिक समाज के करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापना और विसर्जन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब एक हजार लोगों की भागीदारी रही। भगवान सूर्य की प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा बाढ़ जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मुखिया, जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार कुशवाहा, नगर अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष संजय कुमार शाह और विक्की हिंदू समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मल्लिक समाज के करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद विधि-विधान और धूमधाम के साथ भगवान सूर्य की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मुखिया ने कहा कि मल्लिक समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं।

सभी को धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्लिक समाज ने हमेशा सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम किया है। आज समाज के लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने मल्लिक समाज के लोगों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक की सराहना भी की। कार्यक्रम के संयोजक दीपक मल्लिक ने कहा कि मल्लिक समाज को आमतौर पर कोई सम्मानित नहीं करता है। इसी वजह से उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के माध्यम से समाज के लोगों को सम्मानित कराने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने के पीछे समाज को सम्मान और पहचान दिलाने का उद्देश्य भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मृत्यु तक मल्लिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर यह समाज बांस का सूप नहीं बनाएगा तो देशभर में छठ महापर्व का आयोजन संभव नहीं होगा।

ग्रेटर नोएडा में मकान में लगी आग, दो युवकों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के यूसुफपुर चक शाहबेरी में बुधवार को एक मकान में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान में रखा सामान उसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में दो युवक झुलसकर घायल हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।

दमकल कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए आग पर काबू पाया और दोनों घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार को थाना बिसरख पुलिस को यूसुफपुर चक शाहबेरी स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर आग काफी तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही मकान के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान आग की चपेट में आने से दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों की पहचान मोनू केवट (25) और गुड्डू केवट (32) के रूप में हुई है। दोनों आग में झुलस गए थे। दमकल कर्मियों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों घायलों का उपचार कराया जा रहा है। आग लगने के कारण मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है।

भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम कर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव : उपमुख्यमंत्री मौर्य

लखनऊ (एजेंसी)



उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या ममता बनर्जी, ये सभी भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेता भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। चुनावों में जनता अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें जवाब देगी।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या ममता बनर्जी, ये सभी भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। वे ऐसे कई काम कर रहे हैं, जो किसी भी देशभक्त को नहीं करने चाहिए।' मौर्य ने कहा कि कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है और इसके 'युवराज' राहुल गांधी लगातार ऐसी हरकतें करते रहते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, जहां भी चुनाव होंगे, जनता अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें जवाब देगी। गोरखपुर में अखिलेश यादव के 'पीडीए' मार्च पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव गोरखपुर, सैफई या लखनऊ में कहीं भी यात्रा निकाल लें। समाजवादी पार्टी का भविष्य पहले भी अंधकारमय था, आज भी है और आगे भी रहेगा। समाजवादी पार्टी 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के हसीन सपने देख सकती है, लेकिन असल में वह सत्ता में नहीं आ सकती। अखिलेश यादव यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वहीं, राज्य सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता है।

विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के समय यह नैरेटिव बनाया कि भाजपा जीती तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस आधार पर विपक्ष को थोड़ी सफलता मिली थी, लेकिन झूठे आरोपों, तथ्यों और मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर काठ की हंडियां बार-बार नहीं चढ़ सकती हैं। जनता विपक्ष को समझ रही है कि यह सिर्फ झूठे दावे करते हैं और फर्जी व मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, सभी जानते हैं और आम आदमी भी यह महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश का माहौल और लोगों की धारणा बदली है। देश और दुनिया का उत्तर प्रदेश के प्रति नजरिया बदला है। यहां निवेश आया है, कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और विकास तेजी से हो रहा है। यूपी में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में बेहतरीन प्रगति हुई है। जयवीर सिंह ने कहा, दूसरी ओर, लोग 2012 से 2017 के उस दौर को नहीं भूले हैं, जो गुंडागर्दी, अराजकता, जमीन पर कब्जे, वसूली, दंगों, 'एक जिला, एक माफिया' और एक ठप पड़े प्रशासन का समय था, जहां खास माफिया और अपराधी जिलों को चलाते थे। जनता अगली बार विपक्ष के झूठे नारों और झांसे में फंसने वाली नहीं है।

सपा नेताओं ने 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनने का किया दावा

अयोध्या/लखनऊ (एजेंसी)



समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि जनता मान चुकी है कि प्रदेश में विकास, जनकल्याण और खुशहाली केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही संभव है। जब अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे, तब प्रदेश में विकास की नई दिशा तय होगी।

गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित पीडीए मार्च को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने गोरखपुर की धरती को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि इसी भूमि ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक साबित होगा। इस रैली से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और उसकी राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी। पीडीए मार्च के जरिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समानता का संदेश जनता तक पहुंचाएगी। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के मामले पर अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और कथित तौर पर झूठे तथ्यों के आधार पर मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है।

बरेली में गौकशी की तैयारी कर रहे पांच अपराधी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार



बरेली (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में बुधवार रात को पुलिस ने कथित तौर पर कौकशी की तैयारी कर रहे पांच आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो अपराधियों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीन अन्य को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलाह और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। बरेली पुलिस के अनुसार, बुधवार रात को थाना मीरगंज पुलिस शांति व्यवस्था के दृष्टिगत गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की ओर से सूचना दी गई कि कुछ बदमाश ग्राम लभारी के जंगलों में गौकशी की घटना की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया।

बदमाशों की ओर से स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम ने जवाबी आत्मरक्षार्थ की फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल अपराधियों की पहचान बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के निवासी नन्हे उर्फ मतिया और आसिफ कुरैशी के रूप में हुई। आसिफ कुरैशी वर्तमान में रामपुर के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में रह रहा था। दोनों घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तीन अन्य आरोपियों में अशरफ, शेर सिंह और आसन शाह शामिल हैं, जो बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के मंकरा गांव के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों ने 13 नवंबर को लभारी गांव के जंगल में पशु काटने की घटना को स्वीकार किया, जिसके संबंध में थाना मीरगंज पर एफआईआर पंजीकृत है।

'भाजपा राम-कृष्ण की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी', यूपी में 'राधे राधे, कमल खिला दे' नारे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

लखनऊ (एजेंसी)



कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'अब साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान की भक्त नहीं है। यह राम-कृष्ण की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी है। उन्होंने 'राधे राधे, कमल खिला दे' का नारा दिया है, लेकिन उनकी पूजा-अर्चना स्वीकार नहीं होगी

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नारे 'राधे राधे, कमल खिला दे' पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम-कृष्ण की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी है और जनता इन्हें भगवान राम और कृष्ण को बेचने नहीं देगी।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'अब साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान की भक्त नहीं है। यह राम-कृष्ण की पुजारी नहीं, बल्कि व्यापारी है। उन्होंने 'राधे राधे, कमल खिला दे' का नारा दिया है, लेकिन उनकी पूजा-अर्चना स्वीकार नहीं होगी। इस नारे से भाजपा का चाल-चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। जनता इन्हें भगवान राम और कृष्ण को बेचने नहीं देगी।' उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन तय हो चुका है और आगे सीटों के बंटवारे पर बातचीत होनी है। प्रमोद तिवारी ने कहा, यह पहले फैसला हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी।

अब बस यह तय होना बाकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किसकी मदद करेगा और कहां से दोनों को फायदा होगा। हमारा मकसद वही है जो हमारे शीर्ष नेताओं की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना और उत्तर प्रदेश को बीजेपी से मुक्त करना, जो इस राज्य को बर्बाद और तबाह कर रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, दोनों दलों के बीच सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं। वरिष्ठ नेता बैठकर बातचीत कर रहे हैं। दिन प्रति दिन हमारा गठबंधन मजबूत हो रहा है। जल्द ही सारे विषयों पर निर्णय हो जाएगा। हम 2027 में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज जब युवा नौकरियों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जब महिलाएं महंगाई को लेकर अपनी चिंताएं उठाती हैं, तो गैस और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं।

सच बोलना विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार को सच्चाई दिखाना और यह बताना कि जनता क्या चाहती है। आने वाले 2027 के चुनाव साफ कर देंगे कि जनता क्या चाहती है।

आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा है भारत, बेरोजगारी और लचर शिक्षा व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती : राहुल गांधी

देश के युवाओं में बढ़ती निराशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है : राहुल गांधी

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली (एजेंसी)



न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी के साथ संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी के साथ संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। मॉडरेटर लिडिया पॉलग्रीन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में बढ़ती निराशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। पिछले 12 वर्षों में अपने छठे अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी बुधवार (18 नवंबर) को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का भी दौरा करेंगे, जहां वे छात्रों और शिक्षाविदों से संवाद करेंगे।

चुनावी व्यवस्था में धांधली और 'SIR' अभियान के खर्च पर उठाए गंभीर सवाल

'SIR' अभियान के खर्च को बताया अनुमान से 50 गुना ज्यादाः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने इसे सामान्य अभियान से बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस अभियान में जितना पैसा खर्च किया गया, वह सामान्य अनुमान से 20 से 50 गुना तक अधिक था। उन्होंने पूछा कि इतना पैसा आखिर कहां से आया और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

चुनावी नतीजों पर जताया संदेह, सुधार को बताया जरूरीः चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि चुनावों में अचानक 5 लाख वोटों का अंतर (मार्जिन) मिल जाना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास चुनावी नतीजों और धांधली से जुड़े कई सवाल व सबूत हैं, जिन्हें सामने लाने के लिए पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और देश की चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त कर पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है।

युवाओं की निराशा और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी पर जताई चिंता

शिक्षित मध्यमवर्गीय युवाओं में बढ़ रहा मोहभंगः लिडिया पॉलग्रीन द्वारा भारतीय युवाओं की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि औपचारिक शिक्षा हासिल कर चुके मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं में मौजूदा हालात को लेकर गहरी निराशा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस सामाजिक व आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन कर रही है और इसका मूल कारण यही सामने आया है कि युवाओं को आगे कोई स्पष्ट भविष्य नहीं दिख रहा है। माता-पिता की सलाह को नकार रही नई पीढ़ीः राहुल ने समाज में पीढ़ियों के बीच बढ़ते फासले (जेनरेशन गैप) को रेखांकित करते हुए कहा कि करियर के अवसरों को लेकर युवाओं और उनके माता-पिता के बीच दूरी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि आज के युवा पिछली पीढ़ी के अनुभवों पर सवाल उठाते हुए अपने माता-पिता से कह रहे हैं– आप सफल नहीं थे, इसलिए आप हमें वह करने के लिए नहीं कह सकते जो आपने किया, क्योंकि आज के दौर में वह फॉर्मूला काम नहीं करता।

कुवैत में ड्रोन हमलों का अलर्ट, सेना ने एक्टिवेट किया एयर डिफेंस सिस्टम

कुवैत सिटी (एजेंसी)



मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक व सैन्य तनाव के बीच कुवैत में ड्रोन हमलों का हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुवैती सेना ने बुधवार को पुष्टि की कि देश की हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही हैं। सेना के जनरल स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई दे रही तेज धमाकों की आवाजें इन हवाई हमलों को हवा में ही रोकने (इंटरसेप्ट करने) की कार्रवाई का नतीजा हैं। कुवैती आर्मी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, ईरानी मीडिया ने दी विस्फोटों की खबरहवाई हमलों को नाकाम करने में जुटी सेनाः कुवैत आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'कुवैत की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही हैं।'

जनरल स्टाफ के अनुसार, एयर डिफेंस यूनिट्स पूरी सतर्कता के साथ हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में जुटी हुई हैं, जिससे आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरब सूत्रों के हवाले से विस्फोटों का दावाः दूसरी ओर, बीबीसी फारसी से मिली जानकारी के अनुसार, ईरानी मीडिया ने 'अरब सूत्रों' के हवाले से कुवैत में कई विस्फोट होने की खबरें प्रसारित की हैं। बहरीन के बाद अब कुवैत में हलचलः गौरतलब है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा तनाव चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने बहरीन स्थित अमेरिकी रडार ठिकानों पर हमले करने की घोषणा की थी। तेहरान ने इसे केशम और सिरिक सहित खाड़ी के तटीय इलाकों में हुए अमेरिकी हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई करार दिया था। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताः ईरान ने पहले ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उसकी संप्रभुता या ठिकानों पर हमला होता है, तो वह खाड़ी क्षेत्र और उससे बाहर भी मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है।

एशिया-प्रशांत की समृद्धि के लिए सहयोग और मुक्त व्यापार का सेतु बनाएं देश : शी जिनपिंग

बीजिंग (एजेंसी)



चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। शी जिनपिंग ने कहा कि क्षेत्र की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन के गुआंगदोंग प्रांत के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सीईओ शिखर सम्मेलन 2026 को मुख्य संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर एवं सुचारु बनाए रखने के साथ मुक्त और खुले व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने मुक्त व्यापार क्षेत्र एशिया-प्रशांत (एफटीएएपी) की प्रक्रिया को भी लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उनके मुताबिक, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और साझा विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

शी का यह संबोधन ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी चुनौतियों के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और व्यापार को लेकर चर्चा तेज है। 'एपेक सीईओ समिट 2026' का आयोजन शेनझेन में मंगलवार से बुधवार (17-18 नवंबर) को किया गया। चीनी मीडिया के अनुसार, इसमें 21 एपेक अर्थव्यवस्थाओं और 13 गैर-एपेक अर्थव्यवस्थाओं के राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' की 115 कंपनियां भी मौजूद थीं। भाग लेने वालों में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (लगभग 20 प्रतिशत) रही। इन कंपनियों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यावसायिक सहयोग और विकास के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए इसमें हिस्सा लिया। 18-19 नवंबर को यहीं पर एपेक समिट (आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन) का आयोजन हुआ है। चीन का ये शहर एक और वजह से चर्चा में है। यहीं पर समिट से इतर दुनिया के तीन शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे।

रूस के साइबेरिया में विमान हादसा : केमेरोवो क्षेत्र में एन-12 सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोगों की मौत

मॉस्को (एजेंसी)



रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा सैन्य विमान हादसा हो गया। केमेरोवो क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में रूसी सेना का एन-12 मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई।

रूसी सरकारी मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि की है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है, जिसे लेकर रूसी विमानन अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

यागुनोवो गांव के पास हुआ हादसा, सीसीटीवी फुटेज में दिखी आसमान से गिरती चमकती वस्तु

नियमित उड़ान के दौरान गिरा विमानः रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एन-12 सैन्य विमान मंगलवार को अपनी नियमित उड़ान पर था, तभी केमेरोवो क्षेत्र में यह अनियंत्रित होकर जमीन पर आ गिरा। स्थानीय गवर्नर इल्या सेरेड्युक ने बताया कि दुर्घटना यागुनोवो गांव के समीप हुई।

हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त विमान में कोई सैन्य माल लदा था या नहीं। सोशल मीडिया पर सामने आया फुटेजः दुर्घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें दूर आसमान से एक चमकती हुई वस्तु नीचे की ओर गिरती दिखाई दे रही है। दूरी अधिक होने के कारण विमान के जमीन से टकराने का स्पष्ट दृश्य कैद नहीं हो सका। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और बीबीसी ने फुटेज की तारीख व समय की पुष्टि की है, वहीं रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के मिलान से घटनास्थल की भी पुष्टि की है।

आग पर पाया गया काबू, जांचकर्ताओं की मदद में जुटा स्थानीय प्रशासन

घटनास्थल की घेराबंदीः हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में लगी आग पर काबू पा लिया और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। घटनास्थल का दौरा करने वाले गवर्नर सेरेड्युक ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दमकलकर्मी विमान के मलबे के बीच तलाश करते नजर आ रहे हैं और पास ही कई एंबुलेंस तैनात हैं।

जांच में जुटी टीमेंः गवर्नर ने बताया कि एहतियात के तौर पर एक हेलीकॉप्टर और चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा गया है तथा प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता अब विमानन जांचकर्ताओं को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि रूसी सेना एन-12 विमानों का उपयोग सैन्य कर्मियों और हथियारों की आवाजाही के साथ-साथ खोज और बचाव अभियानों में भी करती है।

शिवसेना (यूबीटी) ने अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पर गृह मंत्री की आलोचना की, उद्धव ठाकरे के कोविड रिकॉर्ड का किया बचाव

मुंबई (एजेंसी)

शिवसेना ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 'पाखंड, राजनीतिक मौकापरस्ती' और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के आसपास के 'संदिग्ध' हालात को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में ठाकरे खेमे ने गृह मंत्री शाह की तारीफ को भाजपा के पिछले राजनीतिक व्यवहार के बिल्कुल उलट बताया।

संपादकीय में बताया गया कि अजित पवार के सत्ताधारी गठबंधन के साथ आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने कथित 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले को लेकर उन्हें और पवार परिवार को सबके सामने निशाना बनाया था और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया था। इसमें कहा गया कि पवार परिवार में जेल जाने की धमकी देकर फूट पैदा की गई थी और इसे अजित पवार पर 'मानसिक, राजनीतिक और भावनात्मक' हमला बताया गया। उद्धव ठाकरे कैंप के सबसे तीखे हमले इस वर्ष की शुरुआत में अजित पवार की मौत के हालात पर केंद्रित थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि अजित पवार भाजपा नेतृत्व में गंभीर मानसिक पेरेशानी झेल रहे थे और अपने जानलेवा प्लेन क्रैश से पहले राजनीतिक रास्ता बदलने के बारे में सोच रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया कि विधायक रोहित पवार और दूसरों के द्वारा घटना के आसपास संदिग्ध हालात की ओर इशारा करने वाले सबूत पेश करने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोई पारदर्शी जांच शुरू नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की उद्योगपति कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी

रायपुर (एजेंसी)



छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के कई बड़े कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह से राजधानी रायपुर समेत रायगढ़ और बिलासपुर में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में रायगढ़ के बड़े उद्योगपति कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की जा रही है।

अचानक हुई इस कार्रवाई से प्रदेश के औद्योगिक और कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीमें बुधवार सुबह से ही दोनों उद्योगपतियों के आवास, कार्यालयों और औद्योगिक परिसरों में दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। कमल अग्रवाल से जुड़े रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और बर्बरीक ग्रुप के ठिकानों पर भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। वहीं, बर्बरीक ग्रुप के संचालक श्रवण अग्रवाल के रायपुर स्थित आवास पर भी आयकर टीम ने दबिश दी है। अधिकारियों द्वारा कारोबारी लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल खातों की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, आयकर संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद विभाग ने यह व्यापक कार्रवाई की है। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक छापेमारी के कारणों और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए आयकर विभाग ने 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की कई टीमें गठित की हैं। ये टीमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एक साथ पहुंचकर संबंधित कारोबारी समूहों के ठिकानों पर जांच कर रही हैं। कार्रवाई में भोपाल और रायपुर की आयकर टीमों के भी संयुक्त रूप से शामिल होने की जानकारी सामने आई है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयकर विभाग की टीमों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को भी तैनात किया गया है।

अधिकारियों की मौजूदगी और एक साथ कई ठिकानों पर चल रही जांच के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विभाग को किन दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जानकारी मिली है तथा आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर : कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकी लतीफ को किया ढेर, सीआरपीएफ के डीजी ने दी बधाई

कुलगाम (एजेंसी)

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों की ओर से उसे आत्मसमर्पण का मौका दिया गया था लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सुरक्षा बलों की सफलता पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जीपी सिंह की ओर से बधाई दी गई है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बधाई हो दोस्तों। कुछ डिशेज ठंडी सर्व करने में सबसे अच्छी लगती हैं, ठंड के मौसम में भी।' सूत्रों के मुताबिक, कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ नामक आतंकवादी को घेरा था। एक वीडियो में सैन्य अधिकारी लगातार आतंकी लतीफ से हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील करते दिखे। सेना के एक अधिकारी को आतंकी लतीफ से यह कहते हुए सुना गया, 'हम तुम्हारे साथ हैं।' हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। यह मुठभेड़ एक बड़े तलाशी अभियान के बीच हुई, जो लगातार कुलगाम जिले के कई इलाकों में चल रहा है। इस अभियान के तहत सुरक्षा बल कई गांवों में घर-घर जाकर सघन तलाशी ले रहे हैं। इस संयुक्त अभियान में सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं। अभियान के पहले दिन सोमवार को एक संदिग्ध आतंकी मारा गया था। सुरक्षा बलों ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि कैसे उमर ने अखरान हमले को अंजाम देने में लतीफ भट की मदद की और कैसे लतीफ फिर से सक्रिय हो गया।

बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु, जय श्री महाकाल से गूंजा परिसर



उज्जैन (एजेंसी)

उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का कुमकुम, मावा और भांग से आकर्षक श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बुधवार सुबह चार बजे भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के बाद दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से तैयार पंचामृत भगवान को अर्पित किया गया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। बुधवार को बाबा महाकाल के श्रृंगार की खास बात कुमकुम, मावे और भांग का इस्तेमाल रहा। इन सामग्रियों से भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई और उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल के जयकारे लगाए। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

पंजाब में पराली जलाने के 6,516 मामले दर्ज, 41.70 लाख रुपये मुआवजा वसूला गया

पटियाला (एजेंसी)



पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेशभर में अब तक 6,516 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 6,095 खेतों का निरीक्षण किया गया है। इनमें 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 297 खेतों में नॉन-एएफएल (नॉन-एक्स सीटू) से संबंधित मामले पाए गए हैं। इन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के तहत कुल 2,294 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 41 लाख 70 हजार रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में अब तक 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,096 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा, 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का मामला दर्ज नहीं है।

भुवनेश्वर में युवती ने खुद को लगाई आग, पुलिस ने पूर्व प्रेमी को हिरासत में लिया

भुवनेश्वर (एजेंसी)



ओडिशा के भुवनेश्वर में इन्फो सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती ने खुद को आग लगा ली, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार को एक बयान में बताया कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि पत्थरगड़िया 200 फीट रोड पर एक युवती ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसके बाद, इन्फोसिटी पुलिस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को बचाया। पुलिस ने बताया, पीड़िता को कैपिटल पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार, वह 90 प्रतिशत तक जल गई है। पीड़िता की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है और वह अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़िता पहले नयापल्ली पुलिस स्टेशन इलाके के एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने बताया, खुद को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण रिश्तों से जुड़ी समस्या है।

कुछ महीने पहले ही उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। सूत्रों के अनुसार, महिला पत्थरगड़िया स्थित एक कैफे में अपने पूर्व प्रेमी से मिलने गई थी। वहां उसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ किसी दूसरी लड़की को देखा, जिससे वह भड़क गई और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। वह वहां से चली गई, लेकिन बाद में एक ज्वलनशील पदार्थ लेकर वापस लौटी और कैफे के पास खुद को आग लगाने की कोशिश की। अनुगोल जिले के रहने वाली युवती के पूर्व प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि घटना में उसकी भूमिका का पता लगाया जा सके। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला को वह ज्वलनशील पदार्थ कहां से और कैसे मिला। गौरतलब है कि खुद को आग लगाने की कई घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने पहले ही सख्त निर्देश जारी किए थे कि पेट्रोल और डीजल को प्लास्टिक की बोतलों या अन्य अनधिकृत कंटेनरों में न बेचा जाए।

सीए 'सैंडपेपरगेट कांड' एक फोरम बनाएगा, खिलाड़ियों और स्टाफ के अनुभव गोपनीय रखे जाएंगे

होबार्ट (एजेंसी)



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने घोषणा की है कि वह 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाएगा, ताकि वे अपनी गवाही दोबारा सुन सकें। बोर्ड ने कहा कि केपटाउन घटना की जांच दोबारा नहीं शुरू की जाएगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून ने कहा, 'ध्यान से सोचने के बाद, सीए बोर्ड ने एक ऐसा फोरम बनाने का फैसला किया है जो 2018 में साउथ अफ्रीका की घटनाओं में शामिल खिलाड़ियों और स्टाफ को अपने अनुभव और नजरिए शेयर करने की इजाजत देगा।' उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह खेल के सबसे अच्छे हित में है। लगभग एक दशक से, उन घटनाओं के नतीजे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बारे में बातचीत का हिस्सा रहे हैं।

यह कई लोगों के लिए एक मुश्किल चैप्टर रहा है और, तेजी से, चल रही बहस खेल से ध्यान भटकाने वाली बन गई है। हमारा मानना है कि अब सर्किट ब्रेकर का समय आ गया है। यह फोरम अतीत पर फिर से बात करने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक मौका बनाने के बारे में है जो एक सम्मानजनक माहौल में अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, और हमारे खेल को सुनने के लिए। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट तब सबसे मजबूत होता है जब वह एकजुट होता है। हम उन सभी के प्रति जिम्मेदार हैं जो खेल से प्यार करते हैं कि हम समझ, सम्मान और नजरिए के साथ एक साथ आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। एक पूर्व खिलाड़ी के तौर पर, मैं जानता हू कि क्रिकेट हमें सबसे जरूरी चीजों में से एक देता है, वे रिश्ते जो हम बनाते हैं और वह दोस्ती जो खेल करियर खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है। मेरी उम्मीद है कि यह प्रक्रिया उन कनेक्शन को मजबूत करने में मदद कर सकता है और हमें आगे क्या होने वाला है, इस पर ध्यान देने दे सकता है। डेविड बून ने कहा, मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि वे इस प्रक्रिया को सम्मानपूर्वक और निजी तौर पर आगे बढ़ने दें।

हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि खेल आगे भी बढ़ता रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, पिछले सप्ताह हमने 2018 में केपटाउन टेस्ट में जो हुआ उसके बारे में कई अलग-अलग बातें सुनी हैं। यह खेल और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल और असहज समय रहा है। तब जो हुआ और जो अब भी हो रहा है, उसका उस समय के कल्चर से बहुत कुछ लेना-देना है। एक ऐसा कल्चर जिसे बनाने में सीए का हाथ था। इस बात को एथिक्स सेंटर रिपोर्ट के आने और उसके बाद 42 में से 36 सिफारिशों को अपनाने से पहचान मिली। हमें उस कल्चर पर गर्व है जो टीम ने पिछले आठ सालों में बनाया है। हमारे खिलाड़ी, हमारे लीडर और हमारे कोच इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय पाने के हकदार हैं।

हम सैंडपेपरगेट से जुड़ी घटनाओं से हुए दर्द और तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहें तो - इस समय खेल को नुकसान हो रहा है। यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें एक रास्ता खोजना होगा और हमें ठीक होना होगा। इस प्रोसेस के हिस्से के तौर पर - और ताकि सभी पार्टियां जो चाहें - घटनाओं के बारे में अपनी बात बता सकें, हम एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाएंगे। ग्रीनबर्ग ने कहा, यह एक इंडिपेंडेंट, सुरक्षित और प्राइवेट माहौल में सभी को अपनी बात कहने का मौका है। यह कोई दोबारा जांच नहीं है, इसे दोबारा मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। किसी को भी हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।

यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है। यह याद रखना जरूरी है कि हम उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आठ साल से भी पहले हुई थीं। यह फोरम उन लोगों को आगे आने और घटनाओं और यादों के बारे में अपने वर्जन को गोपनीय माहौल में साझा करने की इजाजत देगा। जांच शुरू न करने के फैसले के बारे में सीए का मानना है कि यह इस बात को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें शामिल सभी लोग कंस्ट्रक्टिव और आपसी सम्मान के साथ बात कर सकें। उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' के प्रकाशित होने के बाद 2018 में केपटाउन टेस्ट में हुआ सैंडपेपरगेट कांड फिर से चर्चा में है। ख्वाजा ने इस बात का दावा किया है कि उस घटना की जानकारी पूरी टीम को थी। ख्वाजा ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पोर्ट एलिजाबेथ में पिछले टेस्ट में भी ऐसा ही किया था।

आईसीसी रैंकिंग : अर्शदीप को मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन का इनाम, टॉम बैंटन ने लगाई लंबी छलांग

दुबई (एजेंसी) न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम अर्शदीप सिंह को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में मिला है। वह 12 स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस हफ्ते गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा सुधार करने वाले खिलाड़ियों में अर्शदीप शामिल हैं। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान 50 ओवर के फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी 15 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि उनके साथी खिलाड़ी काइल जैमीसन 15 स्थान ऊपर चढ़कर 45वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

वहीं, इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम बैंटन को भी ताजा रैंकिंग में फायदा पहुंचा है। उन्होंने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जीत दिलाने वाली शतकीय पारी खेली थी। बैंटन ने 99 गेंदों पर 121 रन बनाए, जो उनका दूसरा वनडे शतक था। उनकी इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने सीरीज में बराबरी की और वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 34 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके साथी खिलाड़ी जो रूट भी टॉप 10 में वापस आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अर्धशतक लगाने के बाद रूट दो स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं।

भारत के खिलाफ मैच में फिलिस्तीन के खिलाड़ियों पर नस्लवाद का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी) भारत ने मंगलवार को कुआलालंपुर में खेले गए एफसी अंडर-17 एशियन कप 2027 क्वालिफायर में फिलिस्तीन को 4-1 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान डल्लालमुऑन गंगटे को नस्लभेदी व्यवहार का सामना करना पड़ा। घटना के कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद भी रेफरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुकाबले में भारत और फिलिस्तीन दोनों टीमें क्वालिफाइंग ग्रुप में टॉप स्पॉट के लिए लड़ रही थीं।

इस वजह से दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रही थीं। इस दौरान फिलिस्तीनी खिलाड़ी बार-बार भारतीय खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से चुनौती देने और परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। विवाद तब बढ़ गया जब फिलिस्तीन के नंबर 19 खिलाड़ी को भारतीय कप्तान डल्लालमुऑन गंगटे के पास नाक पर पंखा झलते हुए देखा गया। इस हरकत को नस्लभेदी माना गया। लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखने के बावजूद, मैच अधिकारियों ने इस घटना पर बिना किसी कार्रवाई के खेल जारी रहने दिया। फिलिस्तीनी खिलाड़ी मोहम्मद जमहूर ने नौवें मिनट के आस-पास एक भारतीय खिलाड़ी को पीछे से दो बार लात मारी और फिर फुटबॉलर के जमीन पर गिरने के बाद उसके हाथ पर पैर पटक दिया। इस घटना के बाद रेफरी ने फिलिस्तीन के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया था।

जहीर खान के साले की सगाई में पहुंचे दिग्गज : अगरकर पत्नी फातिमा के साथ दिखे, नेहरा ने रुश्मा के साथ मचाया धमाल

जयपुर (एजेंसी) क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बनाने वाले कई दिग्गज एक बार फिर साथ नजर आए, लेकिन इस बार मौका कोई मैच नहीं, बल्कि शादी का जश्न था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले यानी सागरिका घटगे के भाई शिवजीत घटगे की सगाई और संगीत समारोह में अजीत अगरकर, आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल ने भी शिरकत की। इस खास शाम की कुछ अनदेखी तस्वीरें अगरकर की पत्नी फातिमा ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इनमें जहीर की बेटे फतेहसिंह के साथ प्यारी बॉन्डिंग से लेकर नेहरा और अगरकर के पारिवारिक अंदाज तक, कई खास पल देखने को मिले। फातिमा अगरकर के साझा किए गए वीडियो में जहीर खान और उनके बेटे फतेहसिंह की एक तस्वीर ने खास ध्यान खींचा।

इसमें जहीर अपने बेटे को गोद में लिए उसके माथे से अपना सिर लगाकर प्यार जताते नजर आ रहे हैं। जहीर की पत्नी सागरिका भी समारोह में मौजूद थीं। वह खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वीडियो में जहीर की फातिमा के साथ भी एक तस्वीर है, जिसमें वह हाथ में गिलास लेकर मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। जहीर खान को हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी पद छोड़ने के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में नजर आए।

अहमदाबाद : 19 से 24 नवंबर के बीच ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर-2026 का होगा आयोजन



अहमदाबाद (एजेंसी)

देश के सभी पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के बीच खेल भावना, शारीरिक क्षमता और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के उद्देश्य से अहमदाबाद में 'तृतीय ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर-2026' का भव्य आयोजन किया गया है।

इसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस के खेल शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 19 नवंबर, 2026 को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुजरात के राज्य पुलिस प्रमुख ज्ञानेन्द्र सिंह मलिक की अध्यक्षता में आयोजित होगा। ज्ञानेन्द्र सिंह मलिक ने टूर्नामेंट की रूपरेखा बताते हुए कहा कि गुजरात पुलिस की मेजबानी में होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता को देशभर से अभूतपूर्व समर्थन मिला है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में देशभर से 890 पुरुष खिलाड़ी और 272 महिला खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

खेल के मैदान में 463 राजपत्रित अधिकारी और 699 गैर-राजपत्रित अधिकारी, पद या रैंक से ऊपर उठकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मेजबान गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीमें इन रोमांचक मुकाबलों के लिए तैयार हैं।

अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बनाई एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह, बेन शेल्टन को हराया

ट्यूरिन (एजेंसी)



अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने राउंड-रॉबिन मुकाबले में बेन शेल्टन को हराकर साल 2026 के एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। जर्मन खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शेल्टन को 6-2, 7-6(4) से हराया। एक घंटे और 34 मिनट तक चले इस मुकाबले में जीत के साथ ही उन्होंने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली।

ज्वेरेव इस प्रतिष्ठित सीजन-एंडिंग टूर्नामेंट में नौवीं बार हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने 2018 में लंदन में और 2021 में ट्यूरिन में ट्रॉफी जीती थी। एटीपी के आंकड़ों के अनुसार, 2018, 2019, 2021 और 2024 के बाद यह पांचवीं बार है जब वह इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। शेल्टन, जो लगातार दूसरे साल इस सीजन-फिनाले में खेल रहे हैं, अब जॉन मैकेनरो ग्रुप में 1-1 की स्थिति में हैं। अमेरिकी खिलाड़ी ने रविवार को आर्थर फिल्स को हराकर एटीपी फाइनल्स में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अब उनका ध्यान गुरुवार को राफेल जोडार के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर है। खचाखच भरे इनल्पी एरिना में ज्वेरेव ने पहले सेट की तेज शुरुआत की। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने पहले ही गेम में शेल्टन की सर्विस तोड़कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली। इसके बाद पांचवें गेम में उन्होंने शेल्टन की सर्विस को एक बार फिर तोड़ा और सेट में 4-1 की बढ़त बना ली।

दूसरा सेट काफी कड़ा रहा, जिसमें सर्विस का दबदबा देखने को मिला। 4-4 के स्कोर पर, 15/40 के मौके पर ज्वेरेव के पास सेट का पहला ब्रेक प्वाइंट था। अगर वह इसे जीत जाते, तो उन्हें मैच के लिए सर्विस करने का मौका मिल जाता। हालांकि, शेल्टन ने शानदार वॉली और फिर एक ऐस की मदद से इन मौकों को टाल दिया और अंततः 5-4 की बढ़त ले ली। एटीपी की रिपोर्ट के अनुसार, ज्वेरेव ने टाई-ब्रेक में अपना संयम बनाए रखा और एक जबरदस्त फोरहैंड शॉट लगाकर सीधे सेटों में जीत हासिल की। इसके साथ ही, इस सीजन में उनकी जीत की संख्या 67 हो गई है, जो टूर पर अब तक की सबसे अधिक जीत है। टूर के सबसे बेहतरीन सर्वरों में से एक के खिलाफ खेलते हुए इनल्पी एरिना में ज्वेरेव की अपनी सर्विस भी उतनी ही शानदार रही। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी सर्विस पर केवल 10 पॉइंट गंवाए (57 में से 47 पॉइंट जीते) और 14 ऐस लगाए, जबकि शेल्टन ने 15 ऐस लगाए।

टॉम लैथम ने किया वेलिंगटन टेस्ट की प्लेइंग इलेवन का खुलासा, बताया कितने तेज गेंदबाजों को देंगे मौका

वेलिंगटन (एजेंसी)



भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले से पहले कीवी कप्तान टॉम लाथम ने टीम की रणनीति का खुलासा कर दिया है। लाथम ने साफ किया है कि न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि टीम के पास तेज गेंदबाजी में अच्छे विकल्प मौजूद हैं और पूरी सीरीज के दौरान खिलाड़ियों के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी संयोजन में बदलाव किया जा सकता है। मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉम लाथम ने कहा कि टीम फिलहाल पूरी सीरीज के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय पहले टेस्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, 'हम तीन तेज गेंदबाज और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाएंगे। हमारे पास कई ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो लगभग पूरी तरह फिट हैं। यह पहले से तय करना मुश्किल है कि कौन सा खिलाड़ी कितने मैच खेलेगा। हम परिस्थितियों और खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए लचीला रुख अपनाएंगे। अगले छह-सात हफ्तों में स्थिति के अनुसार फैसले लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मुख्य फोकस भारत के खिलाफ पहला टेस्ट है।' लाथम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि टीम का ध्यान अंक तालिका के बजाय अपने प्रदर्शन और उन चीजों पर रहेगा, जिन्हें खिलाड़ी मैदान पर नियंत्रित कर सकते हैं। कीवी कप्तान ने कहा, 'वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल मेरा फोकस नहीं है। हम उन चीजों को नियंत्रित करेंगे, जो हमारे हाथ में हैं। हम अपने अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे और जीतने का सर्वश्रेष्ठ मौका हासिल करने की कोशिश करेंगे।'

बुमराह को बताया वर्ल्ड क्लास गेंदबाज

- भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर लाथम ने माना कि वह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। उन्होंने बुमराह के अनोखे गेंदबाजी एक्शन, गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की क्षमता और अलग-अलग परिस्थितियों में प्रभावी प्रदर्शन करने की काबिलियत की तारीफ की।

- लाथम ने कहा, 'बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। कई खिलाड़ियों ने उनका सामना किया है, चाहे वह लंबे प्रारूप का क्रिकेट हो या छोटा प्रारूप। उनका गेंदबाजी एक्शन काफी अलग है और बल्लेबाजों को इसकी आदत डालना आसान नहीं होता। यहां की पिच पर भी वह हमारे लिए बड़ी चुनौती होंगे।'

- उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड ने बुमराह जैसे गेंदबाजों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी की है। हालांकि, टीम का ध्यान सिर्फ बुमराह पर नहीं, बल्कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों पर रहेगा।

स्मैट 2026 : बंगाल ने झारखंड को 7 विकेट से हराया, आंध्र-छत्तीसगढ़ और बिहार ने दर्ज की जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)



सैयद मुश्ताक अली (स्मैट) एलीट 2026 में बुधवार को बंगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड को 7 विकेट से हराया। वहीं, बिहार, आंध्र और छत्तसीगढ़ ने भी जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ बनाम ओडिशाः ग्रुप डी के मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोबोर्ड पर 228 रन लगाए। टीम की तरफ से कप्तान विकल्प तिवारी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली।

उन्होंने 56 गेंदों का सामना करते हुए 119 रनों की दमदार पारी खेली। 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ओडिशा की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 177 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सर्वाधिक 57 रन कार्तिक बिस्वाल ने बनाए। आंध्र बनाम केरलः आंध्र ने ग्रुप सी के मुकाबले में केरल को 29 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आंध्र ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 225 रन बनाए। टीम की तरफ से सीरम वेंकट राहुल ने सर्वाधिक 64 रन बनाए, जबकि शेख रशीद ने 39 गेंदों में 60 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में केरल की टीम 5 विकेट खोकर 196 रन ही बना सकी। केरल की ओर से अब्दुल बासित ने 35 गेंदों में 70 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। संजू सैमसन 13 गेंदों में 26 रन ही बना सके। बंगाल बनाम दिल्लीः ग्रुप ए के मुकाबले में बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को 7 विकेट से हराया।

झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 148 रन बनाए। टीम की तरफ से विराट सिंह ने 37 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए, जबकि शिखर मोहन ने 42 रनों का योगदान दिया। हालांकि, बंगाल ने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की 48 गेंदों में खेली गई 61 और अभिषेक पोरेल की 49 रनों की पारी की बदौलत लक्ष्य को 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बिहार बनाम दिल्लीः बिहार ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 224 रन बनाए।

दिल्ली की ओर से यश धुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों में 16 चौके और 7 छक्कों की मदद से 125 रन बनाए। हालांकि, बिहार की टीम 225 रनों के विशाल लक्ष्य को एक गेंद शेष रहते हुए हासिल करने में सफल रही। बिहार की तरफ से आयुष लोहारुका ने 22 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। वहीं, बिपिन सौरभ ने महज 19 गेंदों में 49 रनों की आतिशी पारी खेली।

धोनी के आईपीएल से संन्यास पर भावुक हुए बुमराह : सूर्यवंशी ने भी खास अंदाज में दी विदाई

नई दिल्ली (एजेंसी)







महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर का अंत क्रिकेट जगत के लिए भावुक पल बन गया है। करीब दो दशक तक इस लीग में अपने नेतृत्व, शांत स्वभाव और मैच फिनिश करने की क्षमता से पहचान बनाने वाले माही अब खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने उन्हें आईपीएल 2027 से पहले टीम का मेंटर नियुक्त किया है। उनके इस नए सफर की शुरुआत से पहले क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, सुरेश रैना, इरफान पठान और दिनेश कार्तिक समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने धोनी के साथ बिताए पलों को याद किया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी खास अंदाज में उन्हें विदाई दी।

बुमराह ने धोनी से क्या कहा?

जसप्रीत बुमराह ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि धोनी उनके पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं और वह उन्हें सबसे ज्यादा आदर्श मानते थे। बुमराह ने धोनी को यादगार पलों के लिए धन्यवाद दिया और उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दीं।

जडेजा ने कही दिल की बात

धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स में 12 सीजन बिताने वाले रविंद्र जडेजा ने बेहद छोटे लेकिन खास संदेश के साथ उन्हें बधाई दी। जडेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आठ का सात के लिए सम्मान हमेशा रहेगा।' जडेजा की इस पोस्ट में दोनों खिलाड़ियों की जर्सी के नंबरों के जरिए उनके रिश्ते और आपसी सम्मान की झलक दिखाई दी। वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने धोनी को भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बताया। उन्होंने लिखा, 'एक कप्तान, एक फिनिशर, दबाव में शांत और संयमित रहने वाले खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। एमएस धोनी, आपने जो विरासत बनाई है, उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'शाबाश एमएस। मुझे विश्वास है कि आपका अपार अनुभव और ज्ञान अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करता रहेगा।'

चहल ने याद किया टीम इंडिया में डेब्यू का दिन

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धोनी के साथ अपने करियर के एक खास पल को याद किया। उन्होंने बताया कि माही ने ही उन्हें भारतीय टीम की डेब्यू कैप सौंपी थी। चहल ने लिखा, 'आपने मुझे भारत की डेब्यू कैप दी थी। यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर संजोकर रखूंगा। आपके मार्गदर्शन, मेंटरशिप और भरोसे ने मेरे सफर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। शुक्रिया माही भाई।

सोनिया-राजीव पर ट्रोलिंग पर भड़कीं सोनाक्षी, कहा- पति और पत्नी का प्यार गलत कैसे हुआ?



अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने राहुल गांधी द्वारा सोनिया गांधी और राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान पर छिड़ी बहस के बीच मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री ने कहा कि उनके आने वाले बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा करते हुए सवाल उठाया कि पति-पत्नी के बीच प्रेम को आखिर सामाजिक गलती के रूप में क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा, 'क्या कुछ लोग सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि सोनिया गांधी लंच के समय राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं?' उन्होंने आगे कहा कि यह दिखाता है प्रेम और वैवाहिक संबंधों को लेकर लोगों की सोच कितनी संकीर्ण हो चुकी है। ऐसे लोग पति-पत्नी के बीच प्रेम को भी गलत नजरिए से देखते हैं, जबकि एक-दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव किसी भी वैवाहिक संबंध का स्वाभाविक हिस्सा है। सोनाक्षी ने आगे लिखा, धत तेरी की, मेरे होने वाले बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। कमर कस लो बच्चों (तुम जहां कहीं भी हो, अभी)।

दरअसल, 16 नवंबर को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव' लॉन्च के दौरान राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के बचपन और परिवार से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पारिवारिक भोजन के दौरान सोनिया गांधी अपने पति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें शुरू में लगता था कि यह हर फैमिली में ऐसा ही होता था, जब तक कि वे अपने दोस्तों के घर नहीं गए। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया और राजनीति में एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की बात करें, तो वह हाल ही में फिल्म 'तू है मेरी किरण' में नजर आई थीं। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल लीड रोल में हैं, जबकि अंकित गुप्ता, शर्लिन सेठ, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य सपोर्टिंग रोल में हैं। **(एजेंसी)**

ऐनी हैथवे : 44 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं अभिनेत्री, न्यूयॉर्क की सड़कों पर नवजात को गोद में लिए आईं नजर

हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और ऑस्कर विजेता ऐनी हैथवे के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं। अभिनेत्री तीसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने अपने पति एडम शुलमैन के साथ तीसरे बच्चे का स्वागत किया है। हाल ही में एक्ट्रेस न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए नजर आई। हालांकि, ऐनी और उनके पति ने अभी तक बच्चे के जन्म को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

न्यूयॉर्क की सड़कों पर बच्चे संग दिखीं ऐनी

ब्लूमकी तरफ से सामने आई तस्वीरों में ऐनी हैथवे अपने बच्चे को डार्क ब्राउन रंग के बेबी कैरियर में लेकर टहलती दिखाई दीं। इस दौरान उन्होंने लैवेंडर रंग का टॉप, उसके ऊपर हल्के रंग का लंबा ट्रेंच कोट, सफेद पैंट और भूरे रंग के बूट्स पहने थे। साथ ही उन्होंने सनग्लासेस और डार्क ब्राउन रंग की कैप लगाई हुई थी। अभिनेत्री का यह कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

दो बेटों की मां हैं ऐनी हैथवे

ऐनी हैथवे और एडम शुलमैन ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों पहले से ही दो बेटों के माता-पिता हैं। उनके बड़े बेटे जोनाथन की उम्र 10 साल और छोटे बेटे जैक की उम्र 6 साल है। अब तीसरे बच्चे के आने से परिवार में खुशियां और बढ़ गई हैं। ऐनी ने इसी साल जून में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा की थी। उन्होंने बारबरा लुईस के गाने 'बेबी, आई एम यॉर्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अभिनेत्री सफेद रंग की खूबसूरत फ्लोई ड्रेस पहने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं। उन्होंने इस खुशखबरी के साथ यह भी जाहिर किया था कि हर प्रेग्नेंसी का सफर आसान नहीं होता और इस बार की खुशखबरी उनके लिए खास है।

तीसरी प्रेग्नेंसी को बताया था 'बजर बीटर'

ऐनी हैथवे ने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी को लेकर खुलकर बात की थी। 14 जुलाई को 'लेट नाइट विद सेठ मेयर्स' शो में पहुंचीं अभिनेत्री ने बताया था कि यह प्रेग्नेंसी उनके लिए एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद सुखद सरप्राइज थी। ऐनी ने मजाकिया अंदाज में अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी को 'बजर बीटर' कहा था। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह होंगी, इसलिए यह उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था।

फिल्म 'वेरिटी' में आई थीं नजर

वर्कफ्रंट की बात करें, तो ऐनी हैथवे हाल ही में फिल्म 'वेरिटी' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ डकोटा जॉनसन और जोश हार्टनेट भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म 2 अक्टूबर को भारत में रिलीज हुई थी। **(एजेंसी)**





मां के हाथ के सिले गाउन से मिस यूनिवर्स तक, ऐसा रहा है सुष्मिता सेन का सफर

साल 1994 भारत के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, जब अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने सिर्फ फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता, बल्कि फिलीपींस की धरती पर मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया था। अभिनेत्री सुष्मिता सेन की कहानी सिर्फ ब्यूटी क्वीन की नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, आत्मसम्मान और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की है। 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में बंगाली परिवार में जन्मी अभिनेत्री सुष्मिता सेन एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिसने देश की सेवा में योगदान दिया है। उनके पिता सुबीर सेन भारतीय वायु सेना के पूर्व विंग कमांडर थे और माता सुष्मा सेन ज्वेलरी डिजाइनर हैं। पिता के वायु सेना में होने के कारण उनका बचपन अनुशासन और अलग-अलग शहरों के माहौल में बीता। पिता (भारतीय वायु सेना के पूर्व विंग कमांडर सुबीर सेन) की पोस्टिंग के चलते उनकी स्कूली शिक्षा सिकंदराबाद के सेंट ऐन हाई स्कूल और नई दिल्ली के वायुसेना गोल्डन जयंती संस्थान में हुई। शुरुआती स्कूली दौर में हिंदी माध्यम की पृष्ठभूमि के कारण वह 16 वर्ष की उम्र तक अंग्रेजी में सहज नहीं थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ बनाई और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई। 18 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। बताया जाता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनकी मां ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। हालांकि, प्रतियोगिता के दौरान जब उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या राय भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, तो उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वे ऐश्वर्या के सामने टिक नहीं पाएंगी। तब उनकी मां ने उन्हें समझाया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा। ऑडिशन और ट्रेनिंग कैंप के बाद, 16 जनवरी 1994 को गोवा में हुए फाइनल में सुष्मिता ने खिताब जीता और आगे चलकर मिस यूनिवर्स 1994 का ताज भी अपने नाम किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह भारत की पहली महिला बनीं। मिस इंडिया जीतने के बाद उन्हें मिस यूनिवर्स के बजाय मिस वर्ल्ड में जाने का सुझाव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने मिस यूनिवर्स में ही जाने का फैसला कायम रखा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि प्रतियोगिता में जाने से पहले अभिनेत्री के पास पासपोर्ट की समस्या और सीमित बजट जैसी चुनौतियां रही थीं। **(एजेंसी)**



नवाजुद्दीन पर दीया मिर्जा का फूटा गुस्सा, यूजर्स ने कहा- नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन है

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने बुधवार को अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने के अनुभव को 'एक बुरे सपने जैसा' बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है और कई यूजर्स इसे पीआर स्ट्रैटजी बता रहे हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना की। अभिनेत्री अपनी पोस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए लिखती हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना मेरे लिए बुरे सपने जैसा है, उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का है और वे बेहद आपत्तिजनक इंसान हैं। दीया मिर्जा ने अपनी इस पोस्ट के पीछे की कोई वजह या संदर्भ अभी तक साझा नहीं किया है। हालांकि, अभी तक न तो दीया मिर्जा ने इस पर कोई सफाई दी है और न ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से कोई जवाब आया है। अभिनेत्री की पोस्ट में कोई स्पष्ट विवरण न होने के कारण सोशल मीडिया यूजर्स इसे किसी आने वाले प्रोजेक्ट या विज्ञापन के प्रमोशन व पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग किसी संभावित विवाद को लेकर हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा, ये भी पीआर ही होगा, आजकल सब वही है। दूसरे यूजर ने लिखा, नवाजुद्दीन के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और दीया मिर्जा के फॉलोअर्स उसके आधे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, आजकल लोग काफी समझदार हो गए हैं और प्रमोशन वाली चीजों को आसानी से पहचान लेते हैं। पीआर टीमों को अब लोगों से सच में जुड़ने के लिए नए और अलग तरीके सोचने होंगे। **(एजेंसी)**

हुआंग की वापसी पर एनवीडिया चेयरमैन ने कहा- उन्हें सीईओ पद पर बहाल करने की योजना नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)



चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने बुधवार को कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की जेनसन हुआंग को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर बहाल करने की कोई योजना नहीं है। जोन्स की यह टिप्पणी कंपनी के सह-संस्थापक हुआंग के उस बयान के कुछ घंटे बाद आयी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि निदेशक मंडल इसे कंपनी के हित में मानता है तो उन्हें इस पद पर लौटने में सम्मान महसूस होगा।

जोन्स ने 2027 की तीसरी तिमाही के नतीजों पर आयोजित बातचीत की शुरुआत में कहा, 'जेनसन हुआंग ने स्वेच्छा से कंपनी के अध्यक्ष, सीईओ और निदेशक मंडल के सदस्य के पदों से इस्तीफा दिया था। एनवीडिया के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उन्हें सीईओ के रूप में बहाल करने की उसकी कोई योजना नहीं है।' जोन्स ने कहा कि हुआंग ने 'कंपनी की आचार संहिता के मानकों और सांस्कृतिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले निजी व्यवहार का खुलासा होने के बाद' स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। हालांकि, 12 नवंबर को इस्तीफे की घोषणा करते समय निदेशक मंडल के बयान में इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। जोन्स ने कहा कि निदेशक मंडल ने स्थायी सीईओ की तलाश की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली कंपनी हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को सौंपी है।

कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'हालांकि, नेतृत्व में यह बदलाव अप्रत्याशित था, लेकिन निदेशक मंडल ने कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों, साझेदारों और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में सोच-समझकर कदम उठाया।' जोन्स ने कहा कि निदेशक मंडल को अंतरिम सीईओ के रूप में क्रेस के नेतृत्व, ईमानदारी और कामकाज संभालने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। एनवीडिया के निदेशक मंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण निगरानी समिति भी गठित की है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों, वरिष्ठ बाहरी सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों का एक चुनिंदा समूह शामिल है। इसका उद्देश्य अमेरिकी सरकार और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ कंपनी के संपर्क को और मजबूत करना है। इससे पहले, मंगलवार देर रात इस्तीफे के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में हुआंग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि यदि चिप विनिर्माता कंपनी का निदेशक मंडल इसे कंपनी के सर्वोत्तम हित में मानता है तो उन्हें सीईओ पद पर लौटने में सम्मान महसूस होगा।

डेरियस खंबाटा ने कहा, टाटा संस पर ट्रस्ट का नियंत्रण ही 'टाटा मॉडल' का सार

मुंबई (एजेंसी)

टाटा ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने मंगलवार को इसके वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का विरोध करने के बाद, अब उसका समर्थन करके अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। एक वरिष्ठ वकील खंबाटा ने श्रीनिवासन और सिंह को लिखे चार पृष्ठ के पत्र में कहा कि टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा संस पर नियंत्रण ही 'टाटा मॉडल' का सार है।

टाटा ट्रस्ट गैर-लाभकारी संगठनों का एक समूह है और देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह की होल्डिंग कंपनी (टाटा संस) में सामूहिक रूप से दो-तिहाई हिस्सेदारी रखता है। पत्र में खंबाटा ने कहा, 'आप टाटा मॉडल के मेरे बचाव को टाटा ट्रस्ट के 'वर्तमान नेतृत्व' द्वारा टाटा संस पर नियंत्रण के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लगातार कहा है, सभी न्यासी समान हैं। टाटा मॉडल का सार टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा संस पर नियंत्रण ही है।' उन्होंने कहा कि टाटा संस, जो टाटा ट्रस्ट की मुख्य संपत्ति है, की सुरक्षा करना प्रत्येक ट्रस्टी का 'वैधानिक कर्तव्य' है। खंबाटा ने कहा कि श्रीनिवासन और सिंह ने 13 नवंबर के अपने पत्र में टाटा संस को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपना रुख बदलने का कोई कारण नहीं बताया। यह नोएल टाटा और टाटा संस प्रबंधन के बीच असहमति का एक प्रमुख बिंदु है। उन्होंने आगे कहा, 'मेरी शिकायत यह है कि आपने बार-बार सूचीबद्धता का विरोध करने के लिए मतदान क्यों किया, लेकिन फिर अचानक अप्रैल, 2026 में अपना रुख बदल लिया।' उन्होंने कहा कि सूचीबद्धता के गुण-दोष पर बहस ट्रस्ट की बैठक में होनी चाहिए, पत्राचार में नहीं।

सोने की कीमत गिरने से स्वर्ण ऋण उद्योग की वृद्धि सुस्त पड़ने की आशंका

कोच्चि (एजेंसी)



सोने की कीमतों में गिरावट के बाद सोने के बदले कर्ज (स्वर्ण ऋण) देने वाले उद्योग की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने और सोने की नीलामी बढ़ने की आशंका है। कर्जदाताओं का जोर अब नए कर्ज देने के बजाय मौजूदा कर्ज और ब्याज की वसूली पर बढ़ रहा है।

हालांकि, सोने के बदले नए कर्ज की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उद्योग को सोने की कीमतों में तेजी के दौरान देखी गई असाधारण वृद्धि जारी रहने की उम्मीद नहीं है। आईआईएफएल फाइनेंस के अध्यक्ष (उधारी) मयंक शर्मा ने कहा कि इस साल स्वर्ण ऋण उद्योग में सोने की नीलामी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछले दो वर्षों में सोने की कीमतें लंबे समय तक स्थिर नहीं रही हैं। उन्होंने कहा, 'सोने की मौजूदा कीमत पर ग्राहकों से कर्ज और ब्याज की वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।'

शर्मा ने कहा कि सोने की कीमतों में गिरावट के बाद कर्जदाता वसूली के प्रयास तेज कर रहे हैं। ऐसे में इस साल पूरे उद्योग में सोने की नीलामी बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही भी इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है। सोने की कीमतों में गिरावट के साथ त्योहारों, शादियों और अन्य मौसमी खर्चों के कारण कर्ज लेने वालों की पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसा होने पर तीसरी तिमाही में वृद्धि सीमित रहने की उम्मीद है।

भारत-जापान साझेदारी दुनिया की समृद्धि के लिए जरूरी : एस जयशंकर

नई दिल्ली (एजेंसी)



विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को इंडिया-जापान इंडो-पैसिफिक फोरम को संबोधित करते हुए भारत-जापान संबंधों को दुनिया के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए योगदान दे रही है।

विदेश मंत्री ने इंडिया-जापान इंडो-पैसिफिक फोरम के नवीनतम संस्करण के लिए वीडियो संदेश जारी किया। फिलीपींस में आसियान-भारत समिट में शामिल होने के बाद विदेश मंत्री जापान पहुंचे। उन्होंने इस फोरम के आयोजन के लिए 'दिल्ली पॉलिसी ग्रुप' और 'जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' के प्रयासों की सराहना की। जयशंकर ने कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्वास और सद्भावना पर टिकी है और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ी है। उन्होंने कहा, दो बड़े एशियाई लोकतंत्र, गतिशील बाजार अर्थव्यवस्थाएं और समुद्री राष्ट्र होने के नाते, भारत और जापान एक स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित इंडो-पैसिफिक के निर्माण के लिए जरूरी हैं। दोनों देश 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' और विजन 'महासागर' पर मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने आर्थिक सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि जापान की मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता और उन्नत तकनीक, भारत की उद्यमशीलता, पैमाने और प्रतिभा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है।

जापान हमारा एक महत्वपूर्ण एफटीए साझेदार है और 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य में योगदान दे रहा है। वहीं, भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि जापानी व्यवसायों को भारत में बनाकर दुनिया के लिए बनाने का अवसर देती है। मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान दोनों ही प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ और भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने की जरूरत को समझते हैं। कनेक्टिविटी, चोक पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में गैप जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस साल जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा का भी उल्लेख किया। कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा लोगों के बीच अधिक संपर्क दोनों देशों की साझेदारी के तहत आगे भी फोकस में रहेंगे। जयशंकर ने बताया कि 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ होगी। इसे 'इंडिया-जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को विभिन्न स्मारक गतिविधियों के केंद्र में रखा जाएगा।